

दैनिक जागरण

स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपदा है

भारत-चीन संबंध

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों की बैठक के लिए प्रस्तावित चीन यात्रा इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है कि यह चीन के साथ संबंध सुधारने के साथ वैश्विक समीकरणों में बदलाव का जरिया भी बन सकती है। इसलिए बन सकती है कि एक तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मनमानी टैरिफ नीति से अनेक देश आजिज आ गए हैं और दूसरे, आतंकवाद के पोषक एवं पहलगाम में आतंकी हमले के जिम्मेदार पाकिस्तान के खिलाफ भारत की साहसिक सैन्य कार्रवाई पर उनका रवैया बहुत हो विचित्र और पाकिस्तानपरस्ती वाला रहा। इसका ताजा प्रमाण ट्रंप का जिहादी सोच वाले पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष आसिम मुनोर से मुलाकात करना रहा। मुनोर पाकिस्तान के शासनाध्यक्ष नहीं हैं, पर सब जानते हैं कि वही वहां के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। ट्रंप ने इस जिहादी जनरल की प्रशंसा के पुल ही नहीं बांधे, ऐसे भी संकेत दिए कि वे पाकिस्तान की घोखेबाजी और उसके आतंकी चेहरे की चुनौतियां अनदेखी कर ईरान के खिलाफ उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो इन दिनों इजरायल के निशाने पर है। अमेरिका ने पहले भी अपने संकीर्ण हितों के लिए पाकिस्तान को गले लगाया है, लेकिन अब ट्रंप का ऐसा करना भारत के लिए चिंता की बात है। हालांकि बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से फोन पर बात करते समय कश्मीर और आपरेशन सिंदूर पर उन्हें खरी-खरी सुनाई, लेकिन लगता नहीं कि वह पाकिस्तानपरस्ती का परित्याग करेंगे। ऐसे में भारत के लिए उनसे सतर्क होना और चीन जैसे देशों के इरायों को टटोलना आवश्यक है।

चीन भी बदले हालात में भारत से संबंध सुधारना चाहता है। वह यह भी जान रहा है कि ट्रंप पाकिस्तान को उसके पाले से निकालना चाहते हैं। पता नहीं ट्रंप ऐसा कर पाएंगे या नहीं, लेकिन वह अच्छा है कि रूस को भी ट्रंप का रवैया नहीं भा रहा है। रूस से भारत के अच्छे संबंध हैं और वे अमेरिका और यूरोप की आपत्ति के बाद भी कायम हैं। रूस शंघाई सहयोग संगठन का महत्वपूर्ण सदस्य है। भारत 20०1 में स्थापित इस संगठन का सदस्य बाद में बना और फिर पाकिस्तान जैसे देश भी उससे जुड़े। यह उल्लेखनीय है कि गलबन में चीनी सेना से खुनी झड़प के बाद भारतीय रक्षा मंत्री पहले बार चीन जा रहे हैं। वहां उनकी द्विपक्षीय मुलाकात अन्य देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ चीनी रक्षा मंत्री से भी हो सकती है। पिछले कुछ समय से भारत-चीन संबंध सुधरते दिख रहे हैं। भारतीय रक्षा मंत्री की चीन यात्रा सीमा विवाद सहित अन्य मुद्दों को भी सुलझाने की राह खोल सकती है, लेकिन भारत को उससे सतर्क भी रहना होगा। वह पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है और सब जानते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले पर उसका रवैया भारत विरोधी ही था।

मृत शिशु की प्रार्थना

उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की बेहतरी के बीच कुछ लोगों की लापरवाही भारी पड़ जा रही है। हाल ही में एक ऐसा मामला हापुड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सामने आया है। यह बताया गया है कि रात में महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो वहां अंधेरा था। महिला के स्वजन ने मोबाइल फोन से वहां रोशनी की। महिला ने इसी समय बेटे को जन्म दिया। यहां भर्ती दूसरी महिला का भी प्रसव इसी अंधियारे में हो हुआ। जन्म लेने के कुछ देर बाद ही दोनों नवजात की हालत बिगड़ने लगी। स्वजन का आरोप है कि वहां मौजूद चिकित्सक ने शिशु को आक्सीजन देने की बात कही, लेकिन बिजली नहीं होने से आक्सीजन भी नहीं मिल पाई। हालात को संवेदनशीलता को देखते हुए चिकित्सक ने दोनों नवजातों को दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया। उस समय अस्पताल में खड़ी एंबुलेंस के चालक से चलने को कहा गया तो उसने यह बताया कि दूसरी एंबुलेंस जाएगी। नाजुक हालत के बीच 45 मिनट की देरी हो गई। हद यह कि जच्चा-बच्चा को जिस एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, उसमें भी आक्सीजन की सुविधा नहीं थी। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि दोनों शिशुओं की मौत हो गई। इस प्रकरण की ठीक से जांच और दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रसव योग्य अस्पताल में इतनी बुनियादी सुविधाएं तो होनी ही चाहिए। जो नवजात दुनिया देखे बिना धराधाम डोड़ गए, वे अब लौटकर नहीं आएंगे, परंतु उनकी प्रार्थना होगी कि जो आगे जन्म लें, उनकी सलामती सुनिश्चित हो। वह हमारी समूची व्यवस्था पर भी सवाल है, लिहाजा सभी को चेतेने की जरूरत है।

नई गणनाओं से बिग बैंग पर उठे सवाल !

प्रदीप

ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी बिग बैंग संबंधी हमारी स्थापित मान्यताओं को चुनौती देने वाली नई गणनाएं सामने आई हैं। यूनिवर्सिटी आफ बान, प्राग और नार्विज के अध्येताओं का कहना है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में बनने वाली दीर्घवृत्ताकार मंडाकिनियां (गैलेक्सीज) कास्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के एक अहम हिस्से की वजह हो सकती हैं- वही सीएमबी जिसे अब तक बिग बैंग सिद्धांत का सबसे मजबूत साक्ष्य माना जाता रहा है। यह आदिम प्रकाश न केवल प्रारंभिक ब्रह्मांड की तस्वीर प्रस्तुत करता है, बल्कि यह इसकी भी व्याख्या करता है कि प्रारंभिक मंडाकिनियां कैसे अस्तित्व में आईं।

शोधकर्ताओं की एक टीम हमारे ज्ञान को अब एक नई दिशा में मोड़ रही है। उनके अनुसार, सीएमबी की तीव्रता का आकलन संभवतः बहुत अधिक किया गया है। यदि यह बात प्रमाणित होती है, तो आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की कई मौलिक धारणाओं पर पुनर्विचार की आवश्यकता होगी। मानक ब्रह्मांडीय माडल के

ब्रह्मांड कीउत्पत्तियानीबिग बैंग संबंधी स्थापित मान्यताओं से इतर व्याख्या सामने आई है

मुताबिक, ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक महाविस्फोट बिग बैंग से हुई थी। उस क्षण के बाद अंतरिक्ष, समय और पदार्थ अस्तित्व में आए और ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। पहले 3.8 लाख वर्षों में यह इतना ठंडा हो गया कि इलेक्ट्रान और प्रोटान मिलकर तटस्थ हाइड्रोजन परमाणु बना सके।

यह महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसके बाद प्रकाश पहली बार स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में यात्रा कर सका। यही वह क्षण था जब सीएमबी की उत्पत्ति हुई- यह प्रारंभिक ब्रह्मांड का पहला प्रकाश था। दावा है कि दीर्घवृत्ताकार मंडाकिनियां, जो ब्रह्मांड में सबसे पहले बनी थीं, शायद इस विकिरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्वयं उत्सर्जित कर रही थीं। शोधकर्ताओं की गणना के अनुसार, कम-से-कम 1.4 प्रतिशत विकिरण का स्रोत ये मंडाकिनियां हो सकती हैं और शायद उससे भी

आर्थिक अस्थिरता भी बढ़ा सकती है यह युद्ध



आदित्य सिन्हा

ईरान और इजरायल टकराव अभी अपनी आरंभिक अवस्था में है।यदि यह लंबा खिंचता है तो भारत समेत विश्व को वित्तीय मोचें पर कहीं ज्यादा बड़े झटके लगेंगे

पश्चिम एशिया में तनाव फिर से भड़ककर सीधे युद्ध में बदल गया। लगता है अस्थिरता ही इस क्षेत्र की पहचान बन गई है। ईरान- इजरायल के बीच सैन्य टकराव बढ़ते ही तेल की कीमतें आसमान चढ़ने लगीं। इस क्षेत्र में व्यापक खेमेबाजी एवं प्रतिद्वंद्विता ने विभाजन की रेखाओं को गहरा कर दिया है। अब तो इजरायल और ईरान, दोनों एक-दूसरे की राजधानी पर बमबारी में लगे हैं। जहां पूरी दुनिया यही उम्मीद लगाए बैठी है कि यह तूफान भी जल्द थम जाए, वहां सच यह है कि लड़ाई का दायारा बढ़ते ही जोखिम भी बढ़ते जायेंगे। इस कारण वैश्विक मोचों पर आर्थिक दुष्प्रभाव आसन्न दिखते हैं। वैसे तो ईरान और इजरायल लंबे समय से छद्म लड़ाई में उलझे हुए हैं, पर अब वह प्रत्यक्ष युद्ध में बदल गई है। घुंघलाती रेखाओं के बीच छिटपुट गलतियां पूरे क्षेत्र को युद्ध की जद में धकेल सकती हैं।

परमाणु संघर्ष के साये को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। ईरान की जिस यूरैनियम संवर्धन इकाई को बमबारी से ध्वस्त किया गया, वह अब भी संचालन की स्थिति में बताई जाती है। कहा जा रहा है कि ईरान महज कुछ हफ्तों के भीतर परमाणु बम बनाने लायक यूरैनियम संवर्धित कर सकता है। इजरायल जिस

तरह ईरान के अन्य परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा है, उसके कारण इसकी आशंका बढ़ गई है कि ईरान प्रतिरोध के साथ संहारक के रूप में भी आक्रामक परमाणु मुद्रा अपना सकता है। यदि ऐसा होता है तो एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो सकता है, जिसमें सऊदी अरब से लेकर तुर्किये तक शामिल हो सकते हैं। लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी परमाणु होड़ के नए सिरे से तेज होने का जोखिम बढ़ सकता है। इजरायल और ईरान से इतर सीरिया भी लड़ाई का एक अखाड़ा पहले से बना है। उसे लेकर तुर्किये और इजरायल भिड़े हुए हैं। असद तुर्किये और पतन के बाद तुर्किये जहां सीरिया में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है, वहां इजरायल को यह रास नहीं आ रहा है। दोनों जुबानी जंग में भी उलझे हैं। इजरायल समर्थित और तुर्किये विरोधी कुर्दिश मिलिशिया भी एक खिलाड़ी है। एक समय खाड़ी देशों और ईरान के बीच छद्म युद्ध का मैदान बना सीरिया अब त्रिकोणीय संघर्ष का मंच बन गया है।

पश्चिम एशिया में सारी उथल-पुथल उस इलाके में चल रही है, जहां से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के तार जुड़े हुए हैं। ईरान के दक्षिणी तट के निकट एक संचरे स्थान होसुज स्ट्रेट से ही विश्व के करीब एक तिहाई तेल की ढुलाई होती



आंधेरा शणगाणू

है। टकराव बढ़ने से इसमें गतिरोध या आपूर्ति के बंद होने का जोखिम बढ़ जाता है। हैरानी नहीं कि ईरान पर इजरायल के हमलों के तुरंत बाद तेल की कीमतें करीब नौ-दस प्रतिशत तक बढ़ गईं। यह यूक्रेन युद्ध के बाद तेल की कीमतों में आई सबसे बड़ी तेजी है। ब्रेंट क्रूड करीब 75 डालर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया। यदि ईरान के तेल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर इजरायली हमले जारी रहें तो यह भाव 100 डालर प्रति बैरल तक भी पहुंच सकता है। यदि कोई मिसाइल सऊदी आयलफील्ड पर गिर जाए या ईरान होरमुज स्ट्रेट बंद कर दे तो स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। तब कीमतें 120 डालर प्रति बैरल को पार कर सकती हैं। बाजार पर बढ़ती तेल कीमतों का असर दिखने लगा है। इजरायली मुद्रा शेकेल दबाव में है तो जार्डन से लेकर मिस्र जैसे तमाम देशों में बांड पर प्रतिफल भी प्रभावित हुआ है। खाड़ी देशों विशेषकर दुबई और अबूधाबी के शेयर बाजार में स्थल एस्टेट, विमान और बीमा कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी जा रही है। निवेशक सोना, चांदी

जैसे सुनिश्चित विकल्पों का रख कर रहे हैं। राजनीतिक जोखिम बढ़ने के साथ ही पूंजी पलायन और अस्थिरता का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। यह तब है, जब यह संकेत अपनी आरंभिक अवस्था में है। यदि यह और ज्यादा बढ़ता है तो वित्तीय मोचें पर कहीं ज्यादा बड़े झटके लगेंगे। कूटनीतिक कवायद ने स्थिति को और अनिश्चित बना दिया है। ट्रंप ने ईरान पर सख्ती बढ़ाने से इजरायल का साथ देना तय किया है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश सतर्कता बरत रहे हैं। ईरान के प्रतिकार में वे भले ही छिपे तरीके से इजरायल का समर्थन करें, पर उन्हें इसकी भी चिंता है कि यह टकराव कहीं उनकी सीमा तक न आ पहुंचे। रियाद यह नहीं भूल सकता कि 2018 में जब ईरान से तेल खरीदने वालों को राहत देने के लिए अमेरिका के अनुरोध पर उसने अपना उत्पादन बढ़ाया, तो कीमतें गिर गई थीं। इस बार खाड़ी देश यह नहीं चाहते।

भारत के लिए ईरान-इजरायल जंग के क्या निहितार्थ हैं? पहला और स्वाभाविक

सेहत संग आजीविका का भी साधन योग

कुछ समय पहले तक जिस योग को ऋषि-मुनियों की साधना और स्वस्थ जीवन का आधार समझा जाता था, आज वह अधिकाधिक लोगों की ओर से अपनाए जाने वाले सेहत के प्रभावी उपाय के साथ तेजी से बढ़ने वाला कारोबार भी है। योग भारत की प्राचीनतम विधाओं में से एक है और इसे अब वैश्विक मान्यता भी मिल गई है। योग को समूचे विश्व के लिए भारत का अनुपम उपहार कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास से 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के संयुक्त राष्ट्र के निर्णय से भारतीय परंपरा की यह जीवन पद्धति विश्व पटल पर स्वीकार की जा रही है। इसे भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव के तौर पर भी देखे जाना चाहिए। योग वह माध्यम है, जिससे भारतीय सभ्यता-संस्कृति का वैश्विक स्तर पर प्रचार-प्रसार हो रहा है। योग एक विचार नहीं, बल्कि भारतीय जीवन पद्धति है, जिसमें भारतीय जीवन मूल्य समाहित हैं। शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य के साथ आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग की आवश्यकता एवं महत्व को जैन, बौद्ध, सिख दर्शन समेत प्रायः सभी भारतीय दर्शनों ने स्वीकार किया है। उनमें योग का महत्व सर्वमान्य है।

199० के प्रारंभ में पश्चिमी देशों में हुए वैज्ञानिक शोधों से यह निकलकर आया था कि आधुनिक जीवनशैली के कारण होने वाली अनेक बीमारियों के प्रभावी उपचार में योग अचूक है। विश्व की श्रेष्ठ नीकरियों की सूची में योग शिक्षक-प्रशिक्षक भी शामिल हैं। आज तमाम देशों में योग प्रशिक्षकों के लिए नीकरी के मौके बढ़ रहे हैं। अमेरिका में एक अनुभवी योग टीचर की औसतन सालाना कमाई 42 हजार डालर से अधिक होती है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन आदि में योग एक बड़े उद्योग का रूप ले चुका है। विश्व में योग परिधर्नों का बाजार करीब 31.1 अरब डालर का और योग मैट का कारोबार 13 अरब डालर का है। योग में वेलेनेस टूरिज्म, योग रिट्रीट आदि का 915 अरब डालर का कारोबार है। इसके अलावा योग को लेकर दुनिया भर में तरह-तरह के एप विकसित कर लिए गए हैं, जिनसे अच्छी कमाई हो रही है। ऐसे एप बनाने वाली देसी-विदेशी कंपनियां का कारोबार अरबों डालर तक पहुंच चुका है। योग की



प्रो. धियेकानंद तिवारी

ताराकंद में विशेष योग शिविर का आयोजन। एपनआइ बढ़ती लोकप्रियता से प्रभावित होकर संस्कृत और हिंदी सीखने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। भाषा सिखाने वाले डुओलिंगों के अनुसार विभिन्न भाषा सीखने वाले तमाम लोग हिंदी सीखना चाहते हैं। भारत के बाहर पहले योग विश्वविद्यालय की स्थापना लास एंजेलिस में की गई थी। योग दिवस शुरू होने का अमेरिका में योग बाजार पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है, इसकी बानगी इन आंकड़ों में दिखती है। 2008 में करीब डेढ़ करोड़ लोग योग करते थे, लेकिन 2016 में यह संख्या बढ़कर 3.67 करोड़ पर पहुंच गई। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था, 'अमेरिका में लोग अपने स्वास्थ्य और समग्र ध्यान में सुधार के लिए योग अपना रहे हैं।' जर्मनी के सामान्य स्कूलों के बच्चों को भी स्वीच्छिक आधार पर योग सिखाया जा रहा है। ब्रिटेन में पहला योग स्कूल भारत में ब्रिटिश राज के एक अधिकारी रह चुके सर पास ड्युयुस ने 1949 में एपिंग में खोला था। 1965 में 'ब्रिटिश व्हील आफ योग' की स्थापना हुई। वहां प्रौढ़ शिक्षा के तहत 1970 के बाद से पूरे

देश में सैकड़ों योग-कक्षाएं भी लगने लगीं और अनेक प्राइवेट स्कूल भी खुलने लगे। योगाध्यास और उससे जुड़ी वस्तुओं-सेवाओं का ब्रिटिश बाजार एक अरब डालर से अधिक आंका जाता है। 1989 में कम्युनिस्ट तानाशाही के अंत और 1993 में स्लोवाकिया के अलग हो जाने के बाद चेक गणराज्य में योग की जड़ें गहराई तक जम गईं। ईरान, अरब देशों और यहां तक कि पाकिस्तान समेत कई इस्लामिक देशों ने भी योग की महत्ता को समझा और उस स्वीकार किया। सऊदी अरब की योग प्रशिक्षक को पद्म सम्मान भी मिल चुका है। योग पंथ, संप्रदाय और क्षेत्र से परे सर्वमान्य हो रहा है। इसका कारण यह है कि उससे लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। खास बात यह है कि स्थाई लाभ मिल रहा है। लोग असाध्य रोगों से भी मुक्त हो रहे हैं। इसी कारण उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है।

भारत में योग का बाजार 490 अरब रुपये का हो चुका है। एक शोध के अनुसार यह जल्द ही 875 अरब डालर तक पहुंच सकता है। भारत में योग और आयुर्वेद से जुड़े उत्पादों का बाजार 12 हजार करोड़ रुपये का हो चुका है। एक सर्वे के अनुसार योग करने वालों की संख्या में 35 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। योग से जुड़े उत्पाद बनाने वाली कंपनियां भी तेजी से बढ़ी हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में योग सीखने वालों की संख्या करीब 25 करोड़ है। अपने देश में ही योग ट्रेनिंग का कारोबार करीब तीन हजार करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है। योग साधना का माध्यम भी है तो कमाई का साधन भी। अपने देश में 300 से लेकर 1500 रुपये तक योग सिखाने की फीस प्रति घंटे के हिसाब से ली जाती है। अमेरिका, आस्ट्रेलिया जैसे देशों में तीन से पांच घंटे तक की फीस तीन-पांच हजार डालर तक है। रूस, चीन, यूरोप के साथ अन्य देशों में बड़ी संख्या में भारतीय ट्रेनर जा रहे हैं और वहां से लोग ट्रेनिंग लेने भारत भी आ रहे हैं। कुल मिलाकर योग स्वास्थ्य के साथ-साथ पूंजी निर्माण का भी साधन बन चुका है।

(लेखक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आंबेडकर पीठ के अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com



ऊर्जा

योग का महत्व

योग भारतवर्ष की अति प्राचीन विद्या है। योग एक ऐसी आध्यात्मिक क्रिया है जो हमारे शरीर, मन एवं आत्मा को परिमार्जित करके हमें ईश्वर के साथ जोड़ती है। महर्षि पतंजलि ने योग का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि चित्त में चलने वाली अनंत वृत्तियों, जन्म-जन्मांतर के मलिन संस्कारों का निरोध करना ही योग है। मन की नकारात्मक आसुरी वृत्तियां ही हमारे जीवन की उन्नति में सबसे बड़ी बाधक हैं। शरीर एवं मन का गहरा संबंध है। मन का जैसा चिंतन होता है, शरीर भी उसी दिशा में आगे बढ़ता है। शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं में वृद्धि का आधार योग ही है। योग क्रियाएं शरीर को परिपुष्टता प्रदान करती हैं। हमारे शरीर को नई आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण करती हैं।

आज की विकृत जीवन शैली से उपजे रोगों का निराकरण योग पद्धति के आचरण से ही संभव होता है। शस्त्रों में उल्लेख है, 'जिसने अपने शरीर को योग रूपी अग्नि में तपा लिया है, उसके शरीर से रोग एवं अकाल मृत्यु भी दूर रहती है।' हमारे वैदिक ग्रंथ इस योग विद्या के आधार स्तंभ हैं। गोरक्ष संहिता में इस योग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वेद रूपी कल्पवृक्ष का फल योगशास्त्र है। इस योगशास्त्र के सेवन से संसार के तीन प्रकार के तापों का भी शमन होता है। योग विशिष्ट ग्रंथ में मुनि वशिष्ठ ने श्रीराम को योग का सूक्ष्म अर्थ बताते हुए कहा है, 'यह योग ही संसार सागर को पार करने की दिव्य नौका है।'

पूरे विश्व ने योग के महत्व को स्वीकार किया है। योगध्यास से मनुष्य के मन में आनंद, ज्ञान, शान्ति, एकाग्रता और शक्ति का संचार होता है। योग मनुष्य को जीवन जीने की कला से परिचित कराता है। मनुष्य के व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग इसी योग पद्धति से खुलता है। आध्यात्मिक शब्दावली में हमारे ऋषियों ने कहा है कि योग ही योग ही आत्मा को आनंद के भंडार परमात्मा से जोड़ता है।

आचार्य दीप चंद भारद्वाज

मेलबाक्स

अछूते नहीं रह सके हैं। कायदे से देखा जाए तो जब अघजले नोट मिले थे, तभी उनकी नीकत में खोट जाग्राहिर हो गया था और उन पर कानून की चोट हो जानी थी, परंतु न्यायाधीश महेन्द्र के विशेषाधिकारों के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से ही न्यायमूर्ति को हटाने की कवायद भी लंबी चलती है, इस तरह तंत्र की खामी का अनुचित फायदा उठाकर वे अपने पद पर बने रहे। लेकिन अब जबकि उन पर लगे आरोप सही साबित हो चुके हैं तो अपेक्षित कानूनी कार्रवाई लेटलतपीर करना उचित नहीं होगा। यथासंभव शीघ्र इस प्रकरण का निराकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे न्यायतंत्र और उसकी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग चुके हैं। पद के दुष्प्रयोग का इससे बड़ा उदाहरण और कहां देखने को मिलेगा? माननीयों के कदाचार संबंधी मामलों में वर्तमान कानून में सुधार की गुंजाइश को नकारा नहीं जा सकता। अन्य भ्रष्ट जजों की भी गहनता से जांच करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।

मोहित सोनी, कुशी, मध्य प्रदेश

आत्मदर्शन की प्रक्रिया

मौन होई क्रिया नहीं, बल्कि एक स्थिति है जहां मन मौन होता है और आत्मा जागृत। यह भारत की हजारों वर्षों की चिंतन-परंपरा का निचोड़ है, जो मनुष्य को केवल स्वस्थ नहीं, समग्र बनाता है। आज का विश्व

भौतिक प्रगति की दौड़ में थक चुका है, मानसिक तनाव, जीवनशैली जनित रोग और सामाजिक विघटन हर कोने में चिंता बन चुका है। ऐसे में योग, भारत की ओर से दिया गया वह सार्ववैश्विक उत्तर है, जो केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि विचारों और संवेदनाओं को भी संतुलन देता है। योग का उद्देश्य न कोई आसन है, न प्रदर्शन। यह तो आत्मदर्शन की प्रक्रिया है, जो भीतर के विक्षोभ को शांति में रूपांतरित करती है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने भीतर के द्वंद्वों को कैसे साधें और बाहरी असंतुलन के बीच भी संतुलन कैसे बनाए रखें। आवश्यकता केवल योग सत्रों की नहीं, योग संस्कृति की है जो विद्यालयों में बच्चों की सोच को विस्तार दे, युवाओं के भीतर संयम के बीज बोए और कार्यस्थलों पर तनाव को समाधान में बदले। ऐसे में योग दिवस पर हम योग को केवल उत्सव नहीं, उद्यम बनाएं। इसे एक अभियान की तरह अपनाएं जिसका उद्देश्य हो आत्मिक संतुलन, सामाजिक समरसता और वैश्विक शांति। भारत का यह ज्ञान विश्व का मार्गदर्शन करे यही योग का वास्तविक अर्थ है।

अमन सिंह गौर, बीएचयू, वाराणसी

इस सभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकपत्र सादर आमंत्रित है। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें: दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा सेक्टर-63, नोएडा ई-मेल: response@jagran.com

भारत-चीन संबंध

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों की बैठक के लिए प्रस्तावित चीन यात्रा इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है कि यह चीन के साथ संबंध सुधारने के साथ वैश्विक समीकरणों में बदलाव का जरिया भी बन सकती है। इसलिए बन सकती है कि एक तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मनमानी टैरिफ नीति से अनेक देश आजिज आ गए हैं और दूसरे, आतंकवाद के पोषक एवं पहलगाम में आतंकी हमले के जिम्मेदार पाकिस्तान के खिलाफ भारत की साहसिक सैन्य कार्रवाई पर उनका रवैया बहुत ही विचित्र और पाकिस्तानपरस्ती वाला रहा। इसका ताजा प्रमाण ट्रंप का जिहादी सोच वाले पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष आसिम मुनोर से मुलाकात करना रहा। मुनोर पाकिस्तान के शासनाध्यक्ष नहीं हैं, पर सब जानते हैं कि वही वहां के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। ट्रंप ने इस जिहादी जनरल को प्रशंसा के पुल हो नहीं बांधे, ऐसे भी संकेत दिए कि वे पाकिस्तान की धोखेबाजी और उसके आतंकी चेहरे की जानबूझकर अनदेखी कर ईरान के खिलाफ उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो इन दिनों इजरायल के निशाने पर है। अमेरिका ने पहले भी अपने संकीर्ण हितों के लिए पाकिस्तान को गले लगाया है, लेकिन अब ट्रंप का ऐसा करना भारत के लिए चिंता की बात है। हालांकि बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से फोन पर बात करते समय कश्मीर और आपरेशन सिंदूर पर उन्हें खरी-खरी सुनाई, लेकिन लगता नहीं कि वह पाकिस्तानपरस्ती का परित्याग करेंगे। ऐसे में भारत के लिए उनसे सतर्क होना और चीन जैसे देशों के झर्राों को टटोलना आवश्यक है।

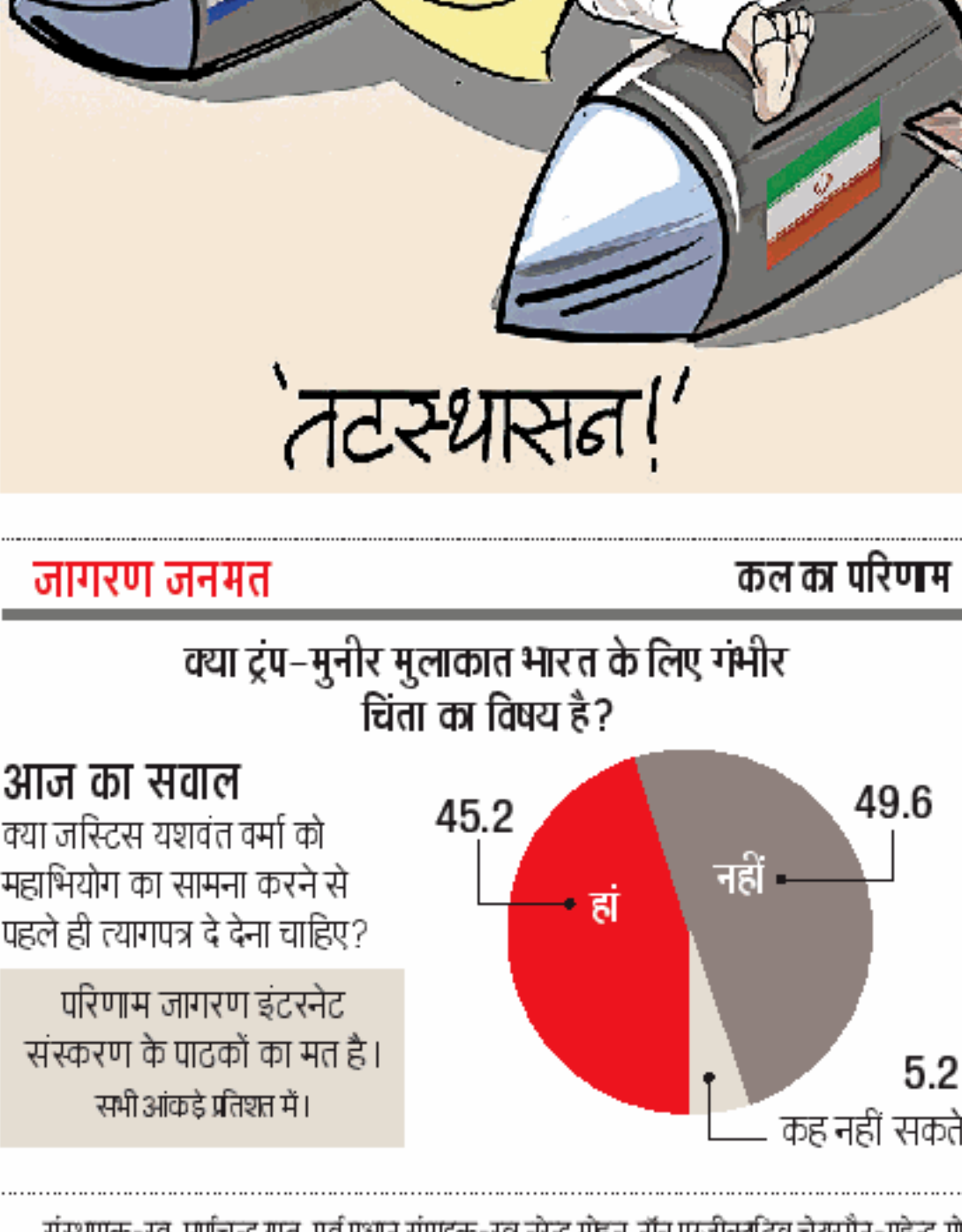
चीन भी बदले हालत में भारत से संबंध सुधारना चाहता है। वह यह भी जान रहा है कि ट्रंप पाकिस्तान को उसके पाले से निकालना चाहते हैं। पता नहीं ट्रंप ऐसा कर पाएंगे या नहीं, लेकिन वह अच्छा है कि रूस को भी ट्रंप का रवैया नहीं भा रहा है। रूस से भारत के अच्छे संबंध हैं और वे अमेरिका और यूरोप की आपत्ति के बाद भी कायम हैं। रूस शंघाई सहयोग संगठन का महत्वपूर्ण सदस्य है। भारत 2001 में स्थापित इस संगठन का सदस्य बाद में बना और फिर पाकिस्तान जैसे देश भी उससे जुड़े। वह उल्लेखनीय है कि गलवन में चीनी सेना से खुनी झड़प के बाद भारतीय रक्षा मंत्री पहली बार चीन जा रहे हैं। वहां उनकी द्विपक्षीय मुलाकात अन्य देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ चीनी रक्षा मंत्री से भी हो सकती है। पिछले कुछ समय से भारत-चीन संबंध सुधरते दिख रहे हैं। भारतीय रक्षा मंत्री की चीन यात्रा सीमा विवाद सहित अन्य मुद्दों को भी सुलझाने की राह खोल सकती है, लेकिन भारत को उससे सतर्क भी रहना होगा। वह पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है और सब जानते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले पर उसका रवैया भारत विरोधी ही था।

उचित व्यवस्था

दिल्ली में अपनी उम्र पूरी कर चुके वाहनों को एक जुलाई से ईंधन देने से रोकने के प्रबंध पूरे हो गए हैं। राजधानी में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने की दिशा में बनाई गई ये योजना अब सिरे चढ़ने जा रही है, जो सर्वथा उचित है। केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली के सभी 520 पंपों पर आटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे लगा दिए जाने की जानकारी देते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि ये कैमरे सेंट्रल डाटा बेस से जुड़े होंगे।

इससे नंबर प्लेट के जरिये वाहनों की उम्र का पता चल जाएगा और उम्र पूरी कर चुके वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। साथ ही ऐसे वाहनों को जब्त कर स्कैप के लिए भेज दिया जाएगा। योजना की घोषणा के बाद से कैमरे लगने में देरी के चलते इसमें विलंब अवश्य हुआ, लेकिन अब सीएक्यूएम के दावे के बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि दिल्ली में इस व्यवस्था को एक जुलाई से लागू कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण वर्ष भर लोगों को परेशान करता है, ऐसे में यह आवश्यक है कि प्रदूषण के कारकों को हर स्तर पर नियंत्रित किया जाए। इस दिशा में सीएक्यूएम की यह पहल स्वागतयोग्य है। वास्तव में बड़ी संख्या में ऐसे वाहन दिल्ली में घड़ल्ले से चल रहे हैं जो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं।

कह के रहेंगे	माधव जोशी
	



आर्थिक अस्थिरता भी बढ़ा सकता है यह युद्ध



आर्दित्य सिन्हा

ईरान और इजरायल टकराव अभी अपनी आरंभिक अवस्था में है। यदि वह लंबा खिंचा है तो भारत सबसे ब्रिच को गितीय तौर पर कहीं ज्यादा बड़े झटके लगेगे

पश्चिम एशिया में तनाव फिर से भड़ककर सीधे युद्ध में बदल गया। लगता है अस्थिरता ही इस क्षेत्र की पहचान बन गई है। ईरान-इजरायल के बीच सैन्य टकराव बढ़ते ही तेल की कीमतें आस्मान चढ़ने लगीं। इस क्षेत्र में व्यापक खेमेबाजी एवं प्रतिद्वंद्विता ने विभाजन की रेखाओं को गहरा कर दिया है। अब तो इजरायल और ईरान, दोनों एक-दूसरे की राजधानी पर बमबारी में लगे हैं। जहां पूरी दुनिया यही उम्मीद लगाए बैठी है कि यह तूफान भी जल्द धम जाए, वहीं सच यह है कि लड़ाई का दायरा बढ़ते ही जोखिम भी बढ़ते जाएंगे। इस कारण वैश्विक मोर्चे पर आर्थिक दुष्प्रभाव आसन दिखते हैं। वैसे तो ईरान और इजरायल लंबे समय से छद्म लड़ाई में उलझे हुए हैं, पर अब वह प्रत्यक्ष युद्ध में बदल गई है। धुंधलाती रेखाओं के बीच छिटपुट गलतियां पूरे क्षेत्र को युद्ध की जद में धकेल सकती हैं। परमाणु संघर्ष के साथे की भी अनदेखा नहीं किया जा सकता।

सेहत संग आजीविका का भी साधन योग

कुछ समय पहले तक जिस योग को ऋषि-मुनियों की साधना और स्वस्थ जीवन का आधार समझा जाता था, आज वह अधिकाधिक लोगों की ओर से अपनाए जाने वाले सेहत के प्रभावी उपाय के साथ तेजी से बढ़ने वाला कारोबार भी है। योग भारत की प्राचीनतम विधाओं में से एक है और इसे अब वैश्विक मान्यता भी मिल गई है। योग को समूचे विश्व के लिए भारत का अनुपम उपहार कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास से 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के संयुक्त राष्ट्र के निर्णय से भारतीय परंपरा की यह जीवन पद्धति विश्व पटल पर स्वीकार की जा रही है। इसे भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। योग वह माध्यम है, जिससे भारतीय सभ्यता-संस्कृति का वैश्विक स्तर पर प्रचार-प्रसार हो रहा है। योग एक विचार नहीं, बल्कि भारतीय जीवन पद्धति है, जिसमें भारतीय जीवन मूल्य समाहित हैं। शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य के साथ आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग की आवश्यकता एवं महत्व को जैन, बौद्ध, सिख दर्शन समेत प्रायः सभी भारतीय दर्शनों ने स्वीकार किया है। उनमें योग का महत्व सर्वमान्य है।

1990 के प्रारंभ में पश्चिमी देशों में हुए वैज्ञानिक शोधों से यह निकलकर आया था कि आधुनिक जीवनशैली के कारण होने वाली अनेक बीमारियों के प्रभावी उपचार में योग अचूक है। विश्व की श्रेष्ठ नैकीरियों की सूची में योग शिक्षक-प्रशिक्षक भी शामिल हैं। आज तमाम देशों में योग प्रशिक्षकों के लिए नैकीरी के मौके बढ़ रहे हैं। अमेरिका में एक अनुभवी योग टीचर की औसतन सालाना कमाई 42 हजार डालर से अधिक होती है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन आदि में योग एक बड़े उद्योग का रूप ले चुका है। विश्व में योग परिधियों का बाजार करीब 31.1 अरब डालर का और योग मैट का कारोबार 13 अरब डालर का है। योग में वेलेनेस टुरिज्म, योग रिट्रीट आदि का 915 अरब डालर का कारोबार है। इसके अलावा योग को लेकर दुनिया भर में तरह-तरह के एप विकसित कर लिए गए हैं, जिनसे अच्छी कमाई हो रही है। ऐसे एप बनाने वाली देशी-विदेशी कंपनियों का कारोबार अरबों डालर तक

पाठकनामा
pathaknama@nda.jagran.com

आतंक को लेकर न हो कोई समझौता

'अमेरिका-पाकिस्तान फिर एक साथ' शीर्षक से लिखे आलेख में श्रीराम चौलिया ने बताया है कि अमेरिका अपने भू-राजनीतिक लक्ष्य को साधने के लिए पाकिस्तान के साथ पूर्व में भी था और आगे भी रहेगा, क्योंकि महाशक्तियों की रणनीति एक देश के हितों तक सीमित नहीं रहती। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि अमेरिका के साथ भारत के संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पाकिस्तान की सीमा अफगानिस्तान, ईरान और चीन से भी लगती है। चीन भारत के पड़ोस में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और उसके अमेरिका के साथ संबंध इन दिनों बहुत अच्छे नहीं हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान को चीन से दूर करने में अमेरिका सफल रहता है तब इसका लाभ भारत की भी मिलेगा, क्योंकि चीन भारत के लिए बड़ी चुनौती है। इसके बावजूद पाकिस्तान के आतंकी संसूबे और उनके क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए खतरे की बात भी अमेरिका को समझानी भी होगी। आतंकवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यह एकदम स्पष्ट होना चाहिए।

मुकेश कुमार मनन, पटन

योग दिवस पर फिर बनेगा रिकार्ड

शरीर को स्वस्थ रखने में योग के बड़े मायने हैं। वर्तमान समय में भागदौड़ भरी जीवनशैली के बीच इसकी आवश्यकता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पास कर पहली बार 21 जून

ईरान की जिस यूरेनियम संवर्धन इकाई को बमबारी से ध्वस्त किया गया, वह अब भी संचालन की स्थिति में बताई जाती है। कहा जा रहा है कि ईरान महज कुछ हफ्तों के भीतर परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम संवर्धित कर सकता है। इजरायल जिस तरह ईरान के अन्य परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा है, उसके कारण इसकी आशंका बढ़ गई है कि ईरान प्रतिरोध के साथ संहारक के रूप में भी आक्रामक परमाणु मुद्रा अपना सकता है। यदि ऐसा होता है तो एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो सकता है, जिसमें सऊदी अरब से लेकर तुर्किये तक शामिल हो सकते हैं। लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी परमाणु होड़ के नए सिरे से तेज होने का जोखिम बढ़ सकता है। इजरायल और ईरान से इतर सीरिया भी लड़ाई का एक अखाड़ा पहले से बना है। उसे लेकर तुर्किये और इजरायल भिड़े हुए हैं। असद शासन के पतन के बाद तुर्किये जहां सीरिया में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है, वहीं इजरायल को यह रास नहीं आ रहा है। दोनों जुबानी जंग में भी उलझे हैं। इजरायल समर्थित और तुर्किये विरोधी कुर्दिश मिलिशिया भी एक खिलाड़ी है। एक समय खाड़ी देशों और ईरान के बीच छद्म युद्ध का मैदान बना सीरिया अब त्रिकोणीय संघर्ष का मंच बन गया है।

पश्चिम एशिया में सारी उथल-पुथल उस इलाके में चल रही है, जहां से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के तार जुड़े हुए हैं। ईरान के दक्षिणी तट के निकट एक संकरे स्थान होरमुज स्ट्रेट से ही विश्व के करीब एक तिहाई तेल की ढुलाई होती है। टकराव बढ़ने से इसमें गतिरोध या आपूर्ति के बंद होने का जोखिम



ताशकंद में विशेष योग शिविर का आयोजन
● एनबिआई
पहुंच चुका है। योग की बढ़ती लोकप्रियता से प्रभावित होकर संस्कृत और हिंदी सीखने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। भाषा सिखाने वाले डुओलिंगों के अनुसार विभिन्न भाषा सीखने वाले तमाम लोग हिंदी सीखना चाहते हैं। भारत के बाहर पहले योग विश्वविद्यालय की स्थापना लास एंजिलिस में की गई थी।

योग दिवस शुरू होने का अमेरिका में योग बाजार पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है, इसकी बानगी इन आंकड़ों में दिखती है। 2008 में करीब डेढ़ करोड़ लोग योग करते थे, लेकिन 2016 में यह संख्या बढ़कर 3.67 करोड़ पर पहुंच गई। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था, 'अमेरिका में लोग अपने स्वास्थ्य और समग्र ध्यान में सुधार के लिए योग अपना रहे हैं।' जर्मनी के सामान्य स्कूलों के बच्चों को भी स्वीच्छिक आधार पर योग सिखाया जा रहा है। ब्रिटेन में पहला योग स्कूल भारत में ब्रिटिश राज के एक अधिकारी रह चुके सर पास ड्युक्स ने 1949 में एपिंग में खोला था। 1965 में 'ब्रिटिश व्हील आफ योगा' की स्थापना हुई। वहां प्रौढ़ शिक्षा के तहत 1970 के बाद से पूरे देश में

पाठकनामा
pathaknama@nda.jagran.com

2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस प्रस्ताव को 177 देशों का समर्थन मिला था। आज भारत विश्व में योग के माध्यम से पहचान बना चुका है। कई देशों में लोग बद्ध-चंद्रक योग दिवस मना रहे हैं। 21 जून 2025 के 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम 'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य' रखी गई है। यह थीम वैश्विक विचार को बढ़ाव देती है, जिसका अर्थ है कि स्वस्थ और टिकाऊ भविष्य के लिए हमारे शह और हम सभी की सेहत आपस में जुड़ा हुआ है। योग दिवस पर इस बार फिर रिकार्ड बनेगा।

मीना धनिया, दिल्ली

भारत की एक और उछाल

नवीन शिक्षा नीति का अब सकारात्मक प्रभाव दिखने लगा है। संख्या की दृष्टि से विश्व में उच्च शिक्षा के संस्थानों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के मामले में भारत 54 संस्थानों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। उसके आगे अब केवल अमेरिका (192), इंग्लैंड (90) एवं चीन (72) हैं। 10 वर्ष पूर्व क्यूएस रैंकिंग में सिर्फ 11 भारतीय संस्थान ही स्थान पा सके थे। यह अद्भुत संयोग है कि भारत विश्व की चौथे सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति भी बन गया है। भारत अब पड़ाई का हब भी बन रहा है। इससे निकट भविष्य में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश का रुख करने वाले छात्रों की संख्या में कमी होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। नौकरी देने के लिहाज से भी क्यूएस रैंकिंग 2026 में भारत के पांच उच्च शिक्षण संस्थानों ने विश्व के टाप 100 में जगह बनाई है। शोध के क्षेत्र में भी आठ भारतीय संस्थानों ने शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त किया है।

धर्मेन्द्र नाथ रस्तोगी, गाजियाबाद



आबधेश राणू

बढ़ जाता है। हैरानी नहीं कि ईरान पर इजरायल के हमलों के तुरंत बाद तेल की कीमतें करीब नौ-दस प्रतिशत तक बढ़ गईं। यह यूक्रेन युद्ध के बाद तेल की कीमतों में आई सबसे बड़ी तेजी है। ब्रेंट क्रूड करीब 75 डालर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया। यदि ईरान के तेल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर इजरायली हमले जारी रहे तो यह भाव 100 डालर प्रति बैरल तक भी पहुंच सकता है। यदि कोई मिसाइल सऊदी आयलफील्ड पर गिर जाए या ईरान होरमुज स्ट्रेट बंद कर दे तो स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। तब कीमतें 120 डालर प्रति बैरल को पार सकती हैं। बाजार पर बढ़ती तेल कीमतों का असर दिखने लगा है। इजरायली मुद्रा शेकेल दबाव में है तो जार्डन से लेकर मिस्र जैसे तमाम देशों में बांड पर प्रतिफल भी प्रभावित हुआ है। खाड़ी देशों विशेषकर दुबई और अबुधाबी के शेयर बाजार में रियल एस्टेट, विमानन और बीमा कंपनियों के शेयर्स में गिरावट देखी जा रही है। निवेशक सोना, चांदी जैसे सुरक्षित या आपूर्ति के बंद होने का जोखिम

जोखिम बढ़ने के साथ ही पूंजी पलायन और अस्थिरता का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। यह तब है, जब यह संकेत अपनी आरंभिक अवस्था में है। यदि यह और ज्यादा बढ़ता है तो वित्तीय मोर्चे पर कहीं ज्यादा बड़े झटके लगेगे।

कूटनीतिक कबायद ने स्थिति को और अनिश्चित बना दिया है। ट्रंप ने ईरान पर सख्ती बढ़ाने और इजरायल का साथ देना तय किया है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश सतर्कता बखत रहे हैं। ईरान के प्रतिकार में वे भले ही दबे-छिपे तरीके से इजरायल का समर्थन करें, पर उन्हें इसकी भी चिंता है कि यह टकराव रियाद तक नहीं भूल तक न आ पहुंचे। रियाद यह नहीं भूल सकता कि 2018 में जब ईरान से तेल खरीदने वालों को राहत देने के लिए अमेरिका के अनुरोध पर उसने अपना उत्पादन बढ़ाया, तो उसकी कीमतें बहुत गिर गई थीं। इस बार खाड़ी देश यह नहीं चाहते।

भारत के लिए ईरान-इजरायल जंग के क्या निहितार्थ हैं? पहला और स्वाभाविक प्रभाव तो ऊर्जा मोर्चे पर

सैकड़ों योग-कक्षाएं भी लगने लगीं और अनेक प्राइवेट स्कूल भी खुलने लगे। योगाभ्यास और उससे जुड़ी वस्तुओं-सेवाओं का ब्रिटिश बाजार एक अरब डालर से अधिक आंका जाता है। 1989 में कम्युनिस्ट तानाशाही के अंत और 1993 में स्लोवाकिया के अलग हो जाने के बाद चेक गणराज्य में योग की जड़ें गहराई तक जम गईं। ईरान, अरब देशों और यहां तक कि पाकिस्तान समेत कई इस्लामिक देशों ने भी योग की महत्ता को समझा और उसे स्वीकार किया। सऊदी अरब की योग प्रशिक्षक को पद्म सम्मान भी मिल चुका है। योग पंथ, संप्रदाय और क्षेत्र से परे सर्वमान्य हो रहा है। इसका कारण यह है कि उससे लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। खास बात यह है कि स्थाई लाभ मिल रहा है। लोग असध्य रोगों से भी मुक्त हो रहे हैं। इसी कारण उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है।

भारत में योग का बाजार 490 अरब रुपये का हो चुका है। एक शोध के अनुसार यह जल्द ही 875 अरब डालर तक पहुंच सकता है। भारत में योग और आयुर्वेद से जुड़े उत्पादों का बाजार 12 हजार करोड़ रुपये का हो चुका है। एक सर्वे के अनुसार योग करने वालों की संख्या में 35 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। योग से जुड़े उत्पाद बनाने वाली कंपनियां भी तेजी से बढ़ी हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में योग सीखने वालों की संख्या करीब 25 करोड़ है। अपने देश में ही योग ट्रेनिंग का कारोबार करीब तीन हजार करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है। योग साधना का माध्यम भी है तो कमाई का साधन भी। अपने देश में 300 से लेकर 1500 रुपये तक योग सिखाने की फीस प्रति घंटे के हिसाब से ली जाती है। अमेरिका, आस्ट्रेलिया जैसे देशों में तीन से पांच घंटे तक की फीस तीन-पांच हजार डालर तक है। रूस, चीन, यूरोप के साथ अन्य देशों में बड़ी संख्या में भारतीय ट्रेनर जा रहे हैं और वहां से लोग ट्रेनिंग लेने भारत भी आ रहे हैं। कुल मिलाकर योग स्वास्थ्य के साथ-साथ पूंजी निर्माण का भी साधन बन चुका है।

(लेखक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आंबेडकर पीठ के अध्यक्ष हैं)
response@jagran.com

अब तो पद छोड़ें

संपादकीय आलेख 'अब तो पद छोड़ें' में जस्टिस यशवंत वर्मा को उचित सलाह दी गई है कि वे इस्तीफा देकर सम्मानजनक अवकाश ग्रहण कर लें। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव मुन्ना ने जांच रिपोर्ट की एक प्रति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलवा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी दी थी। तीन मई को सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने के बाद वहां नकदी की बड़ी मात्रा में गड़िड्यां मिलीं। इन आरोपों में प्रथम दृष्टया सचाई भी पाई गई। दूसरी ओर जस्टिस वर्मा इन आरोपों की खारिज कर इस्तीफा नहीं देने की बात कही है। जस्टिस वर्मा का कहना है कि उन्हें आरोप की जानकारी और अपना पक्ष रखने का उचित मौका नहीं दिया गया। उन्होंने फिर से समीक्षा करने की मांग की है। यह मामला अब न्यायपालिका की आंतरिक जांच प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। दरअसल जस्टिस वर्मा आवश्यक हैं कि पूर्व की भांति इस बार भी महाभियोग का प्रस्ताव नहीं आ पाएगा। कारण यह है कि इसके पीछे सरकार और विपक्ष के बीच समन्वय का अभाव है। संसदीय कानून के मुताबिक, महाभियोग के लिए दोनों सदनों में कम से कम दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ लाए जा रहे महाभियोग प्रस्ताव का विरोध करने का एलान किया है। गुगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

है। भारत अपनी आवश्यकता का 80 प्रतिशत से अधिक तेल आयात करता है, जिसमें बहुलांश हिस्सेदारी खाड़ी देशों की है। यदि कच्चे तेल की कीमतें 100 डालर प्रति बैरल से ऊपर जाती हैं तो पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने के साथ ही महंगाई तेजी पकड़ेगी। इससे परिवहन, निर्माण से लेकर खाद्य वस्तुएं प्रभावित होंगी। दूसरा प्रभाव व्यापार में गतिरोध से जुड़ा है। चूंकि भारत के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा अरब सागर और होसमुज स्ट्रेट के जरिये होता है, इसलिए वहां अस्थिरता बढ़ने का असर उर्वरक, रसायन और इलेक्ट्रानिक्स जैसी अन्य अनेक वस्तुओं की आपूर्ति पर पड़ सकता है। तीसरा बिंदु वित्तीय प्रभाव से जुड़ा है। पश्चिम एशिया में टकराव लंबे खिंचने से रुपये पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे रिजर्व बैंक के लिए मौद्रिक नीति की राह किसलान भरी हो जाएगी। शेयर बाजार भी इसकी तपिश महसूस करेगा। खासतौर से एंविएशन और लाजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों को इसकी मार झेलनी होगी। निवेशकों का भरोसा और पूंजी प्रवाह की दशा-दिशा प्रभावित होने के साथ ही आर्थिकी पर दबाव बढ़ेगा। इस सबसे निपटने के लिए भारत ने अभी भी ठंडा संतुलित कूटनीतिक रणनीति अपनाई है। उसने ईरान, इजरायल और खाड़ी देशों को साधने के प्रयास किए हैं। टकराव बढ़ने पर नई दिल्ली के लिए चुनौतियां भी बढ़ जाएंगी। तटस्थता का भाव रखते हुए रणनीतिक हितों की पूर्ति, भारतवर्षियों की सलामती और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिहाज से यह बड़ी परीक्षा की पड़ी है।

(लेखक लोक-नीति विश्लेषक हैं)
response@jagran.com



योग भारतवर्ष की अति प्राचीन विद्या है। योग एक ऐसी आध्यात्मिक क्रिया है जो हमारे शरीर, मन एवं आत्मा को परिमार्जित करके हमें ईश्वर के साथ जोड़ती है। महर्षि पतंजलि ने योग का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि 'चित्त में चलने वाली अनंत वृत्तियां, जन्म-जन्मान्तर के मलिन संस्कारों का निरोध करना ही योग है। मन की नकारात्मक आसुरी वृत्तियां ही हमारे जीवन व उन्नति में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। शरीर एवं मन का गहरा संबंध है। मन का जाँस चिंतन होता है, शरीर भी उसी दिशा में आगे बढ़ता है। शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं में वृद्धि का आधार योग ही है। योग क्रियाएं शरीर को परिपुष्टता प्रदान करती हैं। हमारे शरीर की नई आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण करती हैं। उसे समृद्ध करती हैं। आज की विकृत जीवन शैली से उपजे रोगों का निराकरण योग पद्धति के आचरण से ही संभव होता है। शास्त्रों में उल्लेख है, 'जिसने अपने शरीर को योग रूपी अग्नि में तपा लिया है, उसके शरीर से रोग एवं अकाल मृत्यु भी दूर रहती है।' हमारे वैदिक ग्रंथ इस योग विद्या के आधार स्तंभ हैं। गोरक्ष संहिता में इस योग की महिमा वर्णन करते हुए कहा गया है कि वेद रूपी कल्पवृक्ष का फल योगशास्त्र है। इस योगशास्त्र के सेवन से संसार के तीन प्रकार के तापों का भी शमन होता है। योग वशिष्ठ ग्रंथ में मूनि वशिष्ठ ने श्रीराम को योग का ज्ञान एवं बताते हुए कहा है, 'यह योग ही संसार सागर को पार करने की दिव्य नौका है।' पूरे विश्व ने आज योग के महत्व को स्वीकार किया है। नियमित योगाभ्यास से मनुष्य के मन में आनंद, ज्ञान, शांति, एकाग्रता और शक्ति का संचार होता है। योग मनुष्य को जीवन जीने की कला से परिचित कराता है। मनुष्य के व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग इसी योग पद्धति से खुलता है। आध्यात्मिक शाब्दबली में हमारे ऋषियों ने कहा है कि योग ही हमारे आत्मा को आनंद के भंडार परमात्मा से जोड़ता है।

आचार्य दीप चंद भारद्वाज

✕ पोस्ट
ट्रंप को अगर नोबेल पुरस्कार दी चाहिए तो बेहतर है कि वे नार्व को धमकाएं कि अगर पुरस्कार नहीं दोगे तो हमला कर दूंगा। कमलेश सिंह@kamleshksingh

ट्रंप जिस तरह दुनिया को क्षति पहुंचाने पर अमाव है, उससे अमेरिका का ही कहीं अधिक नुकसान होता दिख रहा है। अमेरिकी जितनी जल्दी इसे समझ लेंगे, उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। सुहेल सेठ@Suhelseth

संघर्षविराम पर ट्रंप की कपोल-कल्पनाओं को हवा मिलने के लिए भारत सरकार अपने अलावा किसी और को दोष नहीं दे सकती। अब वह एक श्वेत पत्र जारी करे और उसे भारतीय एवं वैश्विक मीडिया को भेजे। उसमें आपरेशन सिंदूर और मिन्हाज के बाद के पूरे घटनाक्रम का विवरण ब्योरा हो। मिन्हाज मर्चेंट@MinhazMerchant

2012 से 2014 के बीच जब काले धन की बात होती थी तो कहा जाता था कि अगर विदेश में जमा काला धन वापस आ जाए तो सबके खाते में 15 लाख रुपये आ सकते हैं। अब लगभग 13 साल बाद रियस बैंकों में जमा पैसों में तैल गुना बढ़ोतरी हो गई है।

आदेश रावल@AadeshRawal

जनपथ

‘दो रोटी’ पर बिक गया जाकर मियां मुनीर, गया ‘ब्रदरहुड’ भाइयों खाव ट्रम्प की खीर! खाव ट्रम्प की खीर पीर खेलें ईरानी, मिल अमरीका-पाक लिखेंगे नई कहानी। देखें मुस्लिम बंधु कि नीयत किसकी खोटी, बेव दिया ईरान खाव के बस दो रोटी!!!

- ओमप्रकाश तिवारी

मोदी सरकार समस्याओं को नियंत्रित करने में नहीं, समूल समाप्त करने में विश्वास करती है

लगातार तीसरी बार जीत के साथ केंद्र में आई नरेन्द्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। भाजपा की ओर से उपलब्धियों की लंबी सूची दिखाई जा रही है तो विपक्ष की ओर से यह जताने की कोशिश हो रही है कि अब सरकार दबाव में आ गई है। जातिवार गणना जैसे मुद्दों पर श्रेय लेने की भी कोशिश हो रही है। जबकि आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद से निपटने के मुद्दे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में भाजपा व सरकार के रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री **अमित शाह** ने तंज किया कि कांग्रेस के नेता इस भ्रम में हैं कि पूरा ब्रह्मांड उनकी वजह से चल रहा है। सच्चाई यह है कि पिछली सरकारों की मंशा और शासन का उनका दृष्टिकोण ही गलत था। दैनिक जागरण के राजनीतिक संपादक **आशुतोष झा** और सहायक संपादक **नीलू रंजन** से बातचीत में शाह कहते हैं कि पिछले 11 वर्षों के सुशासन के कारण ही देश में विश्वास पैदा हुआ है। हमने आधे से ज्यादा रास्ता तय कर लिया है।

● **मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर पार्टी की ओर से कई उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। लेकिन आपकी नजर में पांच मुख्य उपलब्धियां क्या हैं?**
— मुझे संख्या में मत बाँधिये। हर उपलब्धि अहम है, हर किसी का प्रभाव अलग है। पिछले 11 वर्षों में जो भी काम किए गए हैं, उनसे बदलाव आया है, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि 2014 के पहले फैली निराशा की जगह आम लोगों में आशा का संचार हुआ है। भ्रष्टाचार, सीमाओं की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, विदेश में देश की साख, समाज, जीवन में बिखराव और अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति थी। 2014 में, विशेषकर युवाओं के मन में देश की दशा और दिशा को लेकर घोर आशंका थी, वह अधंकार मिट गया। अब 2025 में जब हम बैठें हैं, तब विमर्श इसे लेकर है कि 2047 में हम दुनिया में नंबर बना बनेंगे। यह विश्वास न सिर्फ नेतृत्व का है, बल्कि 140 करोड़ जनता का बन चुका है। और इसके ठोस कारण हैं। आज भारत 1.27 लाख करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादों का निर्माता है। 2023-24 में भारत ने 21,083 करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादों का निर्यात किया, जबकि 2029 तक तीन लाख करोड़ रुपये के उत्पादन और 50,000 करोड़ के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। कुछ वर्ष पहले जो असंभव-सा लगता था, वह आज वास्तविकता बन गया है। भारत अब मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है। 2014-15 में भारत में बिकने वाले मोबाइल फोनों में केवल 26% ही 'मेड इन इंडिया' थे, जबकि फरवरी 2025

तक यह आंकड़ा 99.2% तक पहुंच गया है। ये परिवर्तन सभी क्षेत्र में अथक परिश्रम, दूर दृष्टि और माइक्रो प्लानिंग के साथ स्थिति बदलने के कारण आया है। हर क्षेत्र में यह परिवर्तन जनता भी महसूस करती है और दुनिया भी महसूस करती है।

● **लेकिन 2014 के पहले गरीबी, महंगाई बेरोजगारी जैसे जो मुद्दे थे, वे तो आज भी बुरा क्यों हैं?**
— देखिए, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, जिसका तत्काल समाधान

या संपूर्ण उन्मूलन आपको दृष्टिगोचर नहीं होता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं होता है कि बदलाव नहीं हो रहा है। क्या कोई कह सकता है कि 2014 से 2025 के बीच गरीबों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है या गरीबों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है? 25 करोड़ से ज्यादा लोग मल्टी डायमेंशनल पावर्टी से बाहर आ गए। करीब 80 करोड़ लोगों को विभिन्न योजनाओं में घर, घर में पानी, बिजली, शौचालय, पांच लाख रुपये सालाना तक का इलाज का खर्चा उठाने की योजना और पांच किलो मुफ्त अनाज और गैस का सिलिंडर, ये 11 सालों में पहुंचे हैं। 13 हजार करोड़ से शिल्पकारों, कारीगरों को विश्वकर्मा योजना के तहत मदद मिली और वे पैरों पर खड़े हुए। 13 करोड़ से ज्यादा किसानों को तीन लाख 68 हजार करोड़ रुपये वितरित हुए। जो 70 वर्षों में नहीं पहुंच पाया था वह 2014 के बाद अब तक की गई है। मैं मानता हूं कि इन तीनों मुद्दों पर भी हम 11 वर्षों में आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुके हैं। अभी काम हो रहा है। परिवर्तन और दिखेगा।

● **विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार के विकास के दावे फैलत दावे हैं, उम्कड़ा फायदा जमीन पर लोगों को नहीं मिला है?**
— मैंने जो कुछ आपको बताया, वह ठोस है। क्या विपक्ष झुलहा जाएगा कि 11 वर्षों में भारत 10वीं से दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है? मैं आपको और डाटा दे देता हूं। अर्थव्यवस्था 2.03 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 4.19 ट्रिलियन डॉलर हो गई। सरकार के समावेसी प्रयास का ही नतीजा है कि 11 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 68,572 रुपये से बढ़कर एक लाख 33 हजार 488 रुपये हो गई है। इस दौरान एफडीआई 143 प्रतिशत बढ़कर 308 अरब डॉलर से 749 अरब डॉलर हो गई। मुद्रास्फीति की औसत दर 10.1 प्रतिशत से घटकर 4.6 प्रतिशत रह गई है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट 7.6 अरब डॉलर से 38.6 अरब डॉलर हो गया है। विदेशी मुद्रा भंडार 309 अरब डॉलर से दोगुना होकर 654 अरब डॉलर हो गया है। हाईवे बनाने की गति प्रतिदिन 12 किमी से 21.3 किमी हो गई है। एयरपोर्ट की संख्या 74 से 162 हो गई है। मेट्रो रेल नेटवर्क 248 किमी से 1,000 किमी हो गया है। बैंकिंग सेक्टर की बात करें, तो यूपीए सरकार में बैंकों का एनपीए डबल डिजिट में था, जो घटकर 2.3 प्रतिशत रह गया

है। देश में कुल लेनदेन में डिजिटल लेनदेन की हिस्सेदारी करीब 50 प्रतिशत है। गरीबों के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में किए गए बैंकिंग सुधार और वित्तीय समावेशी विश्व के लिए एक माडल और शोध का विषय है।

● **11 वर्ष में कश्मीर में आतंकवादी, नक्सलवादी और पूर्वोत्तर की अलगाववादी हिंसा में काफी कमी आई। इनसे निपटने में ज्यादा चुनौती कहां आई?**
— सबसे बड़ी चुनौती सरकार की दृष्टिकोण की थी कि इससे निपटने के लिए हमारा प्रयास कैसा होना चाहिए। पहले सरकार का सोच था कि समस्या को बढ़ने नहीं दो, अब हमारा सोच है कि समस्या को समाप्त करो। देश में चुनौती नहीं हो, यह संभव नहीं है। लेकिन आप इसे किस तरह से लेते हैं। अगर आप इस सोच के साथ काम कर रहे हैं कि किसी तरह हमारा कार्यकाल निकल जाए और कोई बड़ी घटना नहीं हो, तो मान लीजिए कि चुनौती का समाधान नहीं होने वाला है। नक्सलवाद को ही लें तो तिरुपति से पशुपतिनाथ तक रेड कारिडोर की कल्पना करते थे जो सबको सच भी लगती थी। 123 जिले नक्सल प्रभावित थे, अब छह जिले रह गए हैं। लगभग समाप्त हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि 31 मार्च 2026 तक यह देश नक्सल समस्या से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। ये तभी होता है, जब पूर्ण उन्मूलन के लिए आप काम करते हैं। पूर्वोत्तर में हिंसा में 70 प्रतिशत कमी आई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुठभेड़ हुई हो, 20 से ज्यादा समझौते किए हैं। 10 हजार से ज्यादा लोग सरेंडर किए हैं। इसकी वजह से कई इलाकों में हिंसा की एक भी घटना नहीं हुई है। अगले साल के आंकड़े आपसे तो शाह 70 प्रतिशत 90 प्रतिशत पहुंच जाएगा।

● **नक्सलवाद सयमुदम दम तोड़ता दिख रहा है, यह हुआ कैसे, क्या रणनीति अपनाई ?**
— सबसे पहले तो हमने उनकी सप्लाई लाइन को काटने का काम किया। पिछले साल 19 अगस्त से यह काम शुरू किया और 20 जून तक

इस पर हमारा पूरा कंट्रोल था। पैसे की, हथियारों की और खाने की सप्लाई लाइन पर। इसके साथ ही लगभग 500 कैप बनाकर सिक्कीमटी वैक्यूम को खत्म किया। हर आठ किमी पर एक कैप है। जवानों को हमने सभी तरह के सूचना तंत्र को दुनिया की अत्याधुनिक तकनीक से लैस कर लगाया। शुरुआत में शंका थी कि शायद मेरे समय मे यह पूरा नहीं हो पाए, लेकिन सबसे पहले झारखंड और बिहार नक्सल मुक्त हो गए। आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के कुछ जिलों में नक्सली जमे हुए थे। झारखंड, मध्यप्रदेश, ओडिशा, बिहार, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र ने मदद की और नक्सल विरोधी अभियान चलाए। पूर्व की भूरेखा बघेल की छत्तीसगढ़ सरकार इसमें मदद नहीं कर रही थी। इसके कारण सभी राज्यों से नक्सली भागकर छत्तीसगढ़ में इकट्ठे हो गए। यह हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया।

● **सुरक्षा के प्रबंधन में जो काम हुए उसे सभी महसूस कर रहे हैं, लेकिन पहलगाम की घटना वड़ा आघात था। इसका सबसे बड़ा सबक क्या रहा?**
— इसका विश्लेषण अलग तरीके से करना चाहिए। एक जमाने में कश्मीर में जो आतंकी मरते थे, उनमें 70 प्रतिशत कश्मीर घाटी से और 30 प्रतिशत बाहर से आते थे, आज वह पांच और 95 का अनुपात हो चुका है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान से भेजे गए आतंकीयों को घटा दें

दिल्ली में 100 दिन में यह सफलता मिली है कि अधिकारियों को हम यह समझाने में सफल रहे हैं कि काम करना पड़ेगा। ये भी बहुत बड़ा काम था

तो भारत में आतंकवाद की समस्या को लगभग समाप्ति के कगार पर ला चुके हैं। घाटी में आतंकी बनने की घटना अब समाप्त हुई और इसका मूल कारण समझना होगा। वहां आतंकवाद का उद्भव अन्यायपूर्ण चुनाव से हुआ था। युवाओं को जोड़ा नहीं गया था। विकास का पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ चुका था। अनुच्छेद 370 के कारण भावना बनी हुई थी कि भारत से अलग हो सकते हैं। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद इस भावना पर पूर्ण विराम लगा। सबको सुनिश्चित हो गया कि यहीं रहना है। दो पंचायत चुनाव, तहसील पंचायत चुनाव, जिला पंचायत चुनाव, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए, कहीं भी एक भी गड़बड़ी की शिकायत हमारे विरोधी भी नहीं कर पाए। हम हारे भी हैं और जीते भी हैं। चुनाव दिल्ली मैनेज करता है, इस छवि को तोड़ने में सफल रहे हैं। लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाया है। मोदी सरकार आने के बाद आधारभूत संरचना के विकास का सबसे ज्यादा फायदा तीन ही हिस्सों में हुआ है, जो उचित भी है। पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर और कश्मीर। ये तीनों पहले इससे वंचित थे। कश्मीर में शैक्षिक संस्थान भी बने। आइआइएम, आइआईटी, एक्स वहां हैं। स्वास्थ्य के संस्थान भी बने और 12 हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश भी हुआ है। 75 साल में 12 हजार करोड़ हुआ था, जबकि 2019 से 2025 के बीच 12 हजार करोड़ निवेश हुआ है। युवाओं में आशा जगी है।

● **आतंकियों के जनाजे पर रोक का भी कुछ असर हुआ है।**
— आज कोई भी आतंकी का जनाजा नहीं निकल सकता। जो जहां मरता है, वहीं दफना दिया जाता है। पाकिस्तान में बैठकर जो आतंकवाद के खेरखाह बने हैं, उनके परिवारों को नौकरियों से हमने निकाल दिया है। जो पथराव में सम्मिलित थे, वे युवा कभी भी सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जहां तक पहलगाम जैसे पाक पोषित आतंकी घटनाओं का सवाल है, उसमें भी आतंकी नीतियों को स्पष्ट रखा है। उरी हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो हमने कठोर जवाब दिया है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आपके समय में क्या होता था। आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस कैसे सवाल पूछ सकती है। मंत्री बदलने के अलावे उन्होंने कभी कुछ नहीं किया।

● **आपरेशन सिंदूर से पहले हमने सिंघु जल समझौता स्थगित किया था, उसे रद्द नहीं किया है। क्या फिर से इसके लागू होने की संभावना है?**
— नहीं, कभी लागू नहीं होगा। ध्यान रखिए कि अंतरराष्ट्रीय समझौते कभी एकतरफा रद्द नहीं होते। स्थगित करने का हमारा अधिकार है, क्योंकि उसकी प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि भारत-पाकिस्तान के अच्छे संबंध और एक-दूसरे के उत्कर्ष के लिए यह समझौता है। जब प्रस्तावना ही आपने खत्म कर दिया तो फिर पीछे कुछ बचता ही नहीं।

● **तीसरे कार्यकाल में वैसे तो कई बड़े फैसले हुए, लेकिन ये आरोप भी लगने लगे कि मोदी सरकार दबाव में काम कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि उनकी वजह से जातिवार गणना की घोषणा हुई है।**
— कांग्रेस के नेता को लगता है कि पूरा ब्रह्मांड ही उनकी वजह से चल रहा है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि पिछले 11 वर्षों से हम 70 करोड़ गरीब के कल्याण के लिए काम कर रहे थे तो ये गरीब कौन हैं। सभी समाज के लोग गरीब हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और

कांग्रेस नेता को लगता है कि पूरा ब्रह्मांड उनकी वजह से चल रहा है तो यह उनकी समस्या है। हमारी सरकार तो शुरू से गरीबों, पिछड़ों, वंचितों के लिए काम कर रही है

● **घुसपैठियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई कई राज्यों में चल रही है। इसे सांप्रदायिक रंग भी देने की कोशिश हो रही है।**
— झूठ से डरकर सच के रास्ते पर चलना छोड़ नहीं सकते। जो घुसपैठिया है, वह घुसपैठिया है और उसे इस देश की भूमि छोड़नी पड़ेगी। हमारा देश धर्मशाला नहीं है। इस देश में आना है तो वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर ही आ सकते हैं। क्या रंग देने कोशिश हो रही है, इससे फर्क नहीं पड़ता। देश की सुरक्षा की प्राथमिकता सबसे ऊपर है।

● **आपकी बातों का अर्थ है कि जहां भाजपा की सरकार है, वहां स्फारालोक बदलाव हो रहा है। दिल्ली में 28 साल बाद भाजपा की सरकार बनी है। आपने 100 दिन का टारगेट दिया था। आप खुश हैं?**
— रेखा जो की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में शुरुआत की है। दिल्ली में एक प्रकार से पूरा देश रहता है। सबके साथ दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रशासन के जुड़ाव की शुरुआत हुई है। पानी की समस्या का लॉग टर्म और शार्ट टर्म, दोनों दृष्टि से समाधान करने की शुरुआत की है। सौविज्ञ की समस्या का भी लॉग टर्म और शार्ट टर्म, दोनों दृष्टि से समाधान किया जा रहा है। यमुना के शुद्धिकरण, विकास, पर्यटन और अवैध कब्जे इन सभी मोर्चों पर एक बढ़िया डिजाइन और समकबद्ध तरीके से नीति बनी है। मेरा मानना है कि पहली बार राजधानी के लोगों को पांच लाख रुपये तक का आयुधान भारत का फायदा इन 100 दिन में ही हमने दे दिया। ई-शासन कार्ड की सुविधा देकर दिल्ली में रहने वाले प्रवासियों को राशन लेने का अधिकार दे दिया। पंचायण की समस्या को हल करने के लिए एक कमेटी का गठन भी किया है, वह कमेटी काम कर रही है। सबसे बड़ी शुरुआत राजस्व नुकसान के सुधार के लिए की गई है। दिल्ली एक ऐसा राज्य है, जहां गांव भी हैं, जिसमें अंग्रेजों के जमाने के लाल डोरे वाले कानून भी हैं, शुद्ध कप से दिल्ली भी है और राजधानी क्षेत्र भी है। इन तीनों में तारतम्यता नहीं होने

के कारण राजस्व का नुकसान होता था। इसमें एकरूपता लाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। 100 दिन में इससे ज्यादा नहीं हो सकता।

● **यहां ट्रिपल इंजन सरकार है। इसीलिए सामंजस्य की जरूरत है। आपको लगता है कि सामंजस्य हो गया है। व्यूसेंसेरी का रुख कैसा है?**
— देखिये, 100 दिन में यह सफलता मिली है कि अधिकारियों को हम यह समझाने में सफल रहे हैं कि काम करना पड़ेगा। यह भी बहुत बड़ा काम था। अब कम से कम ट्रैड-धूप चालू हुई है।

● **मणिपुर के बारे में आपका क्या अफ़तन है, वहां अभी भी तनाव बना हुआ है।**
— पहले दो चीजों को आप अलग कर दीजिए। मणिपुर में आतंकवाद की समस्या नहीं है। मणिपुर में नरस्ली हिंसा की समस्या है। दो नरस्लों के बीच का झगड़ा है, मैतेयी और कुकी। वहां इतने वर्षों से सीमा को खुला रखा गया। न्यायार अस्थिर हुआ, अराजकता की स्थिति बनी। भारत से सटी हुई सीमा पर अब न्यायार सेना का कब्जा नहीं है। अलग-अलग ग्रुप सक्रिय हैं। इससे बड़ी घुसपैठ शुरू हुई। इसके कारण मणिपुर में प्रतिक्रिया हुई और कोर्ट के एक फैसले में चिंगारी भड़काने का काम किया। जब-जब मणिपुर में नरस्ली हिंसा हुई, वह दो-तीन साल में ही थमी है। अभी हिंसा का वातावरण नहीं है, लेकिन हम यह भी नहीं कह सकते कि दोनों समुदायों के बीच मतभेद या

मनभेद को हम समाप्त कर पाए हैं। इसके लिए हम प्रयासरत हैं। पहले दोनों को अलग-अलग बुलाया, फिर संयुक्त रूप से भी बुलाया है और अब राजनीतिक स्तर पर भी बात हो रही है। मुझे लगता है कि कुछ समय में सफलता मिल जाएगी और पूर्ववत स्थिति बहाल होगी।

● **जनगणना की घोषणा हो गई है। आंकड़े कब तक आएंगे और परिसीमन की प्रक्रिया कब शुरू होगी ?**
— आंकड़े 2027 के अंत तक आने की उम्मीद है, वैसे 2027 के मध्य तक भी आ सकते हैं, क्योंकि इस बार हम तकनीक के आधार पर जनगणना कर रहे हैं। आप अपने परिवार की जानकारी खुद ही अपलोड कर सकते हो, ऐसा एक सरल एप भारत की सभी भाषाओं में बनाया है। अपलोड करने के बाद जनगणना कर्मी आपके गांव में जा सकता है और दिल्ली में रहते हो, तो वहां भी आएगा। इसीलिए रिपोर्ट आने में जो पहले पांच-छह साल लगते थे, इस बार पांच-छह महीने में आ जाएगी। पहली बार एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक जनगणना हो रही है।

● **तो 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले परिसीमन की भी संभावना बनती है ?**
— (हंसते हुए) 2029 का चुनाव महिला आरक्षण के साथ होगा।

● **परिसीमन को लेकर दक्षिण के राज्य सवाल खड़े कर रहे हैं, आवादी के मुद्दे को लेकर।**
— स्टालिन अभी यह मुद्दा चुनाव के लिए ही उठा रहे हैं। उनको भी मालूम है कि 2026 के पहले परिसीमन नहीं होना है। ये मुद्दा शास्वत है, तो 2019 से अभी तक क्यों नहीं उठाया। 2025 में क्यों उठा रहे हो, क्योंकि 2026 में चुनाव आना है।

● **सरकार में बहुत-बहुत बड़े फैसले होते हैं, लेकिन संगठन में फैसला नहीं हो रहा है?**
— हो जाएगा, जल्द ही।

● **अस्थाय पद के लिए घोषणा कब तक ?**
— जल्द ही होगी।

● **चर्चा है कि आरएसएस के साथ सम्मय नहीं हो पा रहा है ?**
— नहीं, नहीं। ऐसा कुछ नहीं है।

● **विदेश में खाद्य पदार्थों के कोआपरेटिव स्टोर्स हैं। क्या भारत में वही संभावना है?**
— होने को तो हो ही सकता है। छिटपुट में ऐसे प्रयास हुए हैं। लेकिन संगठित तरीके से योजना बनकर नहीं हुआ है। लेकिन बहुत ही कम समय में बहुत बड़ी कोआपरेटिव बीमा कंपनी भी आएगी। लाइफ और जनरल बीमा दोनों क्षेत्रों में। इसके साथ ही टैक्स भी आएगी। इसके सदस्य टैक्स की मालिक होंगे।

● **आपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के परक़्रम और सफलता को सभी एक्सपर्ट ने रवीकार किया है। लेकिन विपक्ष की ओर से वास-वास सवाल पूछ गया कि देश को उन्मुखान कितना हुआ है?**
— आपने पूछा कि देश को नुकसान कितना हुआ। मेरा मानना है कि इस तरह से सवाल नहीं पूछने चाहिए। जब किसी देश के साथ लड़ते हैं, तब देश की सेना की हीसलाअफजाई करनी चाहिए या निराशा व्यक्त करनी चाहिए। विपक्ष को सेना के

लिए बोलने के लिए दो अच्छे शब्द नहीं मिल रहे हैं।

● **जस्टिस वर्मा के खिताफ महाभियोग को लेकर सभी दलों में सहमत बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन क्या लगता है ऐसा माहौल बना है कि न्यायापालिका की जवाबदेही के लिए किसी विधेयक पर फिर से विचार किया जाना चाहिए ?**
— इस पर सरकार में अभी विचार नहीं हुआ है।

● **संसद के आगामी सत्र में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी?**
— निश्चित रूप से आएगी। मैं तो आशा करता हूं कि सर्वानुमति से आएगी।

● **कुछ लोग इसे जस्टिस शंकर यादव के केस से जोड़ रहे हैं कि उस मामले में ऐसी तत्परता सरकार ने नहीं दिखाई।**
— वह करणन का केस नहीं है। वो व्यवहार (कंडक्ट) का केस है और इसमें चुनी हुई सरकार को निर्णय नहीं करना होता है, सुप्रीम कोर्ट को करना होता है। करणन और कंडक्ट दो अलग-अलग विषय हैं और दोनों में अलग-अलग अधिकारक्षेत्र हैं। अज्ञानियों को क्या जबाब दें।

● **तमिलनाडु में एक जगह किलावी के सिंघु सभ्यता के समान पुरातन होने के दावे के साथ स्टालिन मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं?**
— तमिलनाडु में कोई जगह 700 ईसा पूर्व पुरानी हो, तो इसे लेकर हमें क्या आपत्ति हो सकती है। हम तो खुश होंगे और ढोल पीटेंगे। वह कौन सी बाहर की सभ्यता है, भारत की ही तो सभ्यता है।

● **चार महीने बाद बिहार में चुनाव है। चिरमग पाख्यान अलम राह पर दिख रहे हैं, क्या 2020 की तरह राज्य से अलग हो जाएंगे ?**
— मुझे नहीं लगता है।

● **2024 में उत्तर प्रदेश में अच्छ प्रदर्शन नहीं रहा। क्या 2027 में भाजपा इसमें सुधार कर पाएगी ?**
— भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ जीतीगी।

● **नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाने को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है ?**
— यह हर चुनाव में होता है कि इसको घोषित नहीं करते हो, उसको घोषित नहीं करते हो। वो हम अपने हिसाब से करते हैं। इसमें खबर क्या है।

● **गंगतादेश में जो चल रहा है, उसका देश की आंतरिक सुरक्षा पर कोई असर देख रहे हैं?**
— मैं इतना कह सकता हूं कि पड़ोसी देश में आंतरिक राजनीतिक समस्या हो भी तो भारतीय सीमा के अंदर हम नहीं आने देंगे।

● **अकादी दल एकजुट होने की कोशिश कर रहा है और राज्य में वापस में आने की भी चर्चा है।**
— यह चर्चा सिर्फ मोडिया में ही है।



गलवन टकराव के बाद राजनाथ की चीन यात्रा सीमा विवाद की तपिश करेगी कम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंकाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 25-27 जून के बीच चीन यात्रा पर जाएंगे। रक्षा मंत्री की यह प्रस्तावित यात्रा पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती इलाके में भारत-चीन के बीच गतिरोध के बाकी बचे मुद्दे का हल निकालने की दिशा में अहम साबित हो सकती है। मई 2020 में गलवन घाटी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुए खूनी टकराव में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने की घटना के बाद पहली बार वह चीन जा रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में अक्टूबर 2024 में सैन्य गतिरोध खुल चुके थे दोनों देशों की ओर से हुई बड़ी पहल के बाद राजनाथ की यह यात्रा चीन में पहली भारतीय

एक नजर में

जगदगुरु स्वामी रामभद्राचार्य को डी-लिट की मानद उपाधि

सागर : व. हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षा समारोह में तुलसी पीठ चित्रकूट के संस्थापक जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य को डै-लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौसम खराब होने के कारण नहीं आ सके। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हर क्षेत्र में विकास जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे पास दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तकनीक है। इससे गरीबी, बेरोजगारी को दूर किया जाएगा। (नईदुनिया)

पंजाब नहीं जाने देंगे चिनाव का पानी: उमर

जागरण ● **जम्मू**: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को चिनाव नदी का पानी पंजाब के रास्ते राजस्थान ले जाने का केंद्र सरकार का प्रस्ताव रास नहीं आया है। शुक्रवार को उन्होंने सरकार को इसकी अनुमति नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि यहां की नदियों पर फैला हक जम्मू-कश्मीर का है। पहले चिनाव जम्मू की प्यास बुझाया। फिर हम दूसरी की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब ने हमें बहुत तरसाया है। (राबू)

‘लोस चुनावों में कुल व्यय का 45% भाजपा ने किया खर्च’

नई दिल्ली, प्रेढ़ : चुनाव अधिकार के निकाय ‘सोसिएशन फर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स’ (एडीआर) ने शुक्रवार को कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने लगभग 1,494 करोड़ रुपये खर्च किए, जो कुल चुनावी व्यय का 44.56 प्रतिशत है। इसके बाद कांग्रेस का स्थान है जिसने 620 करोड़ रुपये या कुल व्यय का 18.5 प्रतिशत खर्च किया।

एडीआर ने कहा कि उसने 32 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के रिकार्ड का विश्लेषण किया। इन पार्टियों ने 16 मार्च से छह जून, 2024 के बीच लोकसभा चुनाव के साध-साध हुए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम विधानसभा चुनावों के दौरान कुल 3,352.81 करोड़ रुपये खर्च किए। इस खर्च में राष्ट्रीय दलों का योगदान 2,204 करोड़ रुपये (65.75 प्रतिशत) के साथ रहता है। रिपोर्ट के अनुसार, ‘धक्कित खुल बच में से राष्ट्रीय दलों को 6,930.246 करोड़ रुपये

- एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने 25 जून को चीन यात्रा पर जाएंगे रक्षा मंत्री

- बैठक से इतर राजनाथ की चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून से बातचीत की संभावना



राजनाथ सिंह ● फाइल फोटो

जवान देश की सीमाओं की तरह करें शरीर और मन की रक्षा
राबू, जागरण ● **जम्मू**: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को सेना के जवानों से कहा कि आप अपने शरीर और मन की रक्षा भी उसी निष्ठा से करें, जैसे देश की सीमाओं की करते

मंत्रिस्तरीय यात्रा भी होगी। एससीओ में चीन और भारत के साथ ही रूस, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाक,

ईरान और बेलारूस शामिल हैं। संभावनाएं हैं कि बैठक से इतर राजनाथ की चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून से बात होगी।

आंबेडकर के अपमान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर रहा महागटबंधन

सिवान में नीला अंगवस्त्र ओढ़ मंच पर पहुंचे मोदी, एससी मतदाताओं को दूरगामी संदेश

रमण शुक्ला ● जगदगण

पटना: बिहार दौरे पर शुक्रवार को सिवान के जसौली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अनुसूचित जाति के मतदाताओं को साधने का भरपूर प्रयास किया। लालटेन राज की याद दिलाते हुए, गत दिनों राजद प्रमुख लालू यादव की जन्मतिथि (11 जून) पर अनुसूचित समाज के कर्णधार रहे बाबा साहेब डा. भीमराव आंबेडकर की तस्वीर के अपमान को देखते हुए नीला टुपट्टा ओढ़ विशाल पंडाल में प्रवेश कर दूरगामी संदेश दिए। पीएम कई बार पंजा और लालटेन का उल्लेख कर अनुसूचित जाति के अपमान के लिए कांग्रेस और राजद को दोषी ठहराने से नहीं चूके। आंबेडकर के अपमान को लेकर बिहार भाजपा के नेता राजद के विरुद्ध नौ दिनों से अभियान छेड़े हुए हैं। मोदी ने उसे धार देने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी।

ठेठ भोजपुरी से संबोधन की शुरुआत कर क्षेत्रीय लोगों का दिल जीतने का प्रयास किया। बुजुर्गों से मुखातिब मोदी ने कहा कि आपने मिलकर बिहार में जंगलराज का सफाया किया है। यहां के हमारे नीजवानों ने तो 20 वर्ष पहले के बिहार की बदहाली सिर्फ किस्सों और कथाओं में ही सुनी है। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे



सिवान मे जनसभा के दौरान पीएम आवास योजना के लाभार्थी को घर की प्रतीकात्मक चाबी सौंपते पीएम मोदी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी उपस्थित रहे ● आइएनएस

बिहार के लोग मेहनतकश और स्वाभिमानी : मोदी

जार्स, सिवान : पीएम मोदी ने बिहार के सिवान की सभा में कहा कि बिहार के लोग मेहनतकश और स्वाभिमानी हैं, लेकिन पंजे (कांग्रेस) और लालटेन (राजद) की सरकारों ने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। जंगलराज लाने वाले मौका देख रहे हैं। संसाधनों पर कब्जा करना चाह रहे हैं। इनसे कौंसो

दूर रहने की जरूरत है। कहा कि बाबा साहेब को मैं दिल में रखता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश के नेतृत्व में बिहार विकास की पटरी पर लौट रहा रहा है। उन्होंने ‘मेक इन इंडिया’ के तहत सारण के मंदीरा स्थित रेल कारखाना में निर्मित अत्याधुनिक लोकोमोटिव इंजन को हरी झंडी दिखाई।

को टुंग के सीजफायर के अदृश पर क्यों रोका: राबू पटना के अनुसार राजद नेता तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेसबार्ता कर पूछा कि आपरेशन सिंदूर में आतंकियों व पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की ओर अग्रसर करने को टुंग के सीजफायर के अदृश पर क्यों रोका गया? हमारे मामलों में पंचायत करने वाला यह टुंग होता कौन है?

कैशमी का रक्षात, भारतीय सेना

- आम आदमी पार्टी ने 168 दिन और भाजपा ने 139 से 154 दिनों की देश से दखिल किया विवरण

(93.08 प्रतिशत) और क्षेत्रीय दलों को 515.32 करोड़ रुपये (6.92 प्रतिशत) प्राप्त हुए। यह विश्लेषण अनिवार्य व्यय विवरण पर आधारित है, जिसे राजनीतिक दलों को आम चुनाव के 90 दिनों के भीतर और राज्य चुनाव के 75 दिनों के भीतर चुनाव आयोग के पास दखिल करना होता है। एडीआर को पता चला कि इन्हें देश से दखिल किया गया। आम आदमी पार्टी (आप) का विवरण 168 दिन देश से दखिल हुआ और भाजपा का 139 से 154 दिनों के बाद, जो राज्य पर निर्भर है। केवल कांग्रेस ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों

के लिए एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत की। चुनावी खर्च की सूची में प्रचार सबसे ऊपर रहा। इस मद में पार्टियों ने 2,008 करोड़ रुपये खर्च किए, जो उनके कुल घोषित व्यय का 53 प्रतिशत से अधिक है। यात्रा व्यय 795 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इसके बाद उम्मीदवारों को एकमुश्त भुगतान 402 करोड़ रुपये का स्थान रहा। पार्टियों ने वरचुअल कैमैन पर 132 करोड़ रुपये और अपने उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को प्रकाशित करने पर 28 करोड़ रुपये खर्च किए।

प्रचार पर 32 राजनीतिक दलों के कुल खर्च में से 1,511.30 करोड़ रुपये या 75.25 प्रतिशत राष्ट्रीय दलों ने और 496.99 करोड़ रुपये या 24.75 प्रतिशत क्षेत्रीय दलों ने खर्च किए। यात्रा व्यय भी स्टार प्रचारकों पर काफी हुआ था। यात्रा पर खर्च किए गए 795 करोड़ रुपये में से 765 करोड़ रुपये (96.22 प्रतिशत) पार्टी के हार्ड-प्रोफाइल चेहरों को लाने-ले जाने में खर्च किए गए, जबकि अन्य नेताओं पर सिर्फ 30 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

एडीआर ने पारदर्शिता पर कई चिंताएं जताई हैं। रिपोर्ट तैयार होने के समय राकांपा, माकपा, झामुमो और शिवसेना (यूनाईटेड) सहित 21 दलों के स्टेटमेंट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं थे। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा में 2024 में हुए विधानसभा चुनावों के लिए राजसी (आरबी), आजपू, केसी (एम) के व्यय विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

‘स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी कि नागरिक बीमार न पड़े, इलाज सस्ता मिले’



- केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा- देश में डाक्टरों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि
- बोले-पीएम मोदी ने 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख का मुफ्त इलाज दिया

<< बेंगलुरु में आदिचुंचनागिरी विश्वविद्यालय परिसर के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते गृह मंत्री अमित शाह ● आइएनएस

और उसके इलाज की लागत है। लिहाजा, प्रशासन को गरीबों के इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि मोदी जब प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने 60 करोड़ गरीबों को पांच लाख रुपये तक मुफ्त इलाज प्रदान करके इसे पूरा किया।”

शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने स्वास्थ्य की समस्या को समग्र दृष्टिकोण से संबोधित किया है। इसमें 12 करोड़ घरों में शौचालयों का निर्माण, फिट इंडिया आंदोलन, योग दिवस, मिशन इंड्रघनुष, पोषण अभियान, आयुष्मान भारत और भारतीय जनऔषधि परियोजनाओं

सहकारिता कम पूंजी में ज्यादा मुनाफे का माध्यम : शाह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्रीय गृह एवं सहकारित मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने देश भर की सहकारी इकाइयों का डाटा एकत्र कर लिया है। इसके जरिये यह पता चल गया है कि कहां-कहां इस क्षेत्र में खामियां हैं। इसी आधार पर योजनाएं बनाई जा रही हैं। शाह अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष पर मुंबई

में शुक्रवार को नेफेड की संसदीय को संबोधित कर रहे थे। शाह ने कहा कि सहकारिता कम पूंजी में अधिक मुनाफा और रोजगार का माध्यम है। वहीं मुंबई राबू के अनुसार मुंबई महानगरपालिका व निकाय चुनावों से पहले शाह ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। कहा कि इन दलों ने मुंबई को भगवान के भरोसे छोड़ दिया था।

का समावेश किया गया है। हर साल देश में 1.18 लाख एमबीबीएस डाक्टर हो रहे हैं। शाह ने कहा कि देश में डाक्टरों की संख्या बढ़ने के लिए बड़े प्रयास किए गए हैं। 2014 में देश में सात एम्स थे और अब 23 एम्स हैं और मेडिकल कालेजों की

संख्या 387 से बढ़कर 780 हो गई है। 2014 में 51,000 एमबीबीएस सीटें थीं, आज 1,18,000 हैं और पीजी सीटों की संख्या 31,000 थी आज यह 74,000 है। हर साल देश में 1,18,000 एमबीबीएस डाक्टर और 74,000 डबल ग्रेजुएट डाक्टर निकल रहे हैं।”

अफ्रीकी देश को निर्यात होने वाले रेल इंजन में कई विशेषताएं



सारण जिले में पीएम द्वारा वरचुअल खान्गी देने के बाद रेल इंजन को हरी झंडी दिखाती लोको पायलट श्वेता कुमारी ● लौकट्य फैक्ट्री पब्लिश

जार्स, जागरण, छपरा: बिहार के सारण जिले के मढ़ौरा स्थित रेल कारखाने में निर्यात को तैयार 4500 हासों पावर वाला लोकोमोटिव रेल इंजन कई विशेषताओं से भरे हैं। इस इंजन को अफ्रीकी देश गिनी की रेल पटरियों और वहां के वातावरण के अनुरूप तैयार किया गया है। 27 जून को दो लोकोमोटिव रेल इंजन विशाखापट्टनम के मुद्रा पोर्ट के रास्ते अफ्रीकी देश गिनी गणराज्य को भेजे जाएंगे। भारतीय रेलवे और वेबटेक लोकोमोटिव कंपनी का अफ्रीकी देशों से 143 लोकोमोटिव रेल इंजन आपूर्ति को लेकर करार हुआ है। पीएम मोदी ने सिवान के जसौली से निर्यात किए जाने वाले इंजन की वरचुअल खानगी की।

रेल डीजल इंजन कारखाना के पीआरओ संजन नटराजन ने बताया कि इंजन के केबिन में रेफ्रिजरेटर, एसी यूनिट, माइक्रोवेव ओवन की व्यवस्था है। भारत में ब्राड गेज 1090 एमएम का है, जबकि गिनी के सीमांदू में स्टैंडर्ड गेज हाइट 876 एमएम है। इसे अफ्रीका के एक गांव ‘कोमा’ का नाम दिया गया है।

चुनाव आयोग के वीडियो फुटेज नष्ट करने के निर्देश, गलत सूचनाएं फैलाने की आशंका

नई दिल्ली, प्रेढ़ : चुनाव आयोग (ईसी) ने अपने वीडियो फुटेज का दुरुपयोग कर चुनाव को लेकर ‘दुष्प्रचार’ फैलाने की आशंका के चलते राज्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि किसी चुनावी परिणाम को 45 दिनों के भीतर अदालत में चुनौती नहीं दी जाती है, तो चुनाव प्रक्रिया में इस्तेमाल हुए सीसीटीवी कैमरा, वेबकास्टिंग और वीडियो फुटेज को नष्ट कर दिया जाए।

30 मई को सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को भेजे गए एक पत्र में चुनाव आयोग ने कहा कि उसने चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को रिकार्ड करने के लिए कई रिकार्डिंग उपकरणों का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। इनमें फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी कैमरे और वेबकास्टिंग आदि शामिल हैं। हालांकि, चुनावी कानून

एसी रिकार्डिंग करने की अनिवार्यता नहीं रखते हैं। हालांकि आयोग इन्हें चुनावी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में आंतरिक प्रबंधन उपकरण के रूप में उपयोग करता है।

आयोग ने कहा, “हाल ही में इस चुनावी सामग्री का दुरुपयोग कर इंटरनेट मीडिया पर गलत सूचनाएं फैलाने और दुष्प्रचार करने के लिए इसका संदर्भ से इतर उपयोग किया गया है। यह दुरुपयोग चुनावी प्रक्रिया को रिकार्डिंग को सहजने की समीक्षा करने को विवश करता है। अब

आयोग ने अपने राज्य चुनाव प्रमुखों को बताया है कि चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के सीसीटीवी डाटा, वेबकास्टिंग डाटा और फोटोग्राफी को केवल 45 दिनों के लिए ही सुरक्षित रखा जाएगा। आयोग ने निर्देशित किया कि यदि किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में कोई चुनाव याचिका दायर नहीं की जाती है, तो उस डाटा को नष्ट किया जा सकता है।” कोई भी व्यक्ति संबंधित उच्च न्यायालय में 45 दिनों के अंदर चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली ‘चुनाव याचिका’ दायर कर सकता है।

इस बीच, नागपुर में कांग्रेस नेता नाना पटोले ने चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज नष्ट करने के निर्देश से लगता है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग में साठगांठ हो गई है।

गढ़वाली त्यंजनों का आनंद

पर्यटन नगरी समेत आसपास के होटल-होम स्टे में आप मंडुवे की रोटी, चैसू, फणू, भांग की चटनी, झंगोरे की खीर आदि गढ़वाली व्यंजनों का आनंद भी ले सकते हैं।



अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए खोजें करें।

सिक्किम में नाथुला के रास्ते कैलास-मानसरोवर यात्रा फिर शुरू

जार्स, सिलीगुड़ी: पांच साल तक बंद रहने के बाद सिक्किम के नाथुला के रास्ते कैलास-मानसरोवर यात्रा शुक्रवार से फिर से शुरू हो गई है। सिक्किम के प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में 50 तीर्थयात्रियों का पहला जल्था नाथुला से चीन की ओर खाना हुआ। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने हरी झंडी दिखाकर जल्थे को खाना किया। प्रशासनिक सुत्रों के अनुसार कैलास यात्रा के लिए 50-50 यात्रियों के 10 दलों को अनुमति दी गई है।

भारत-चीन डोकलाम विवाद और उसके बाद गलवन संघर्ष और कोविड महामारी के कारण सिक्किम के रास्ते कैलास-मानसरोवर यात्रा बंद थी। शुक्रवार को जो दल कैलास के लिए खाना हुआ, उसे सिक्किम में पांच दिन रुकना पड़ा ताकि वह वहां के मौसम के साथ तालमेल बिठा सके।

लैंसडौन की पहाड़ियों पर बांज-बुरांश की छांव में लें ट्रेकिंग का आनंद

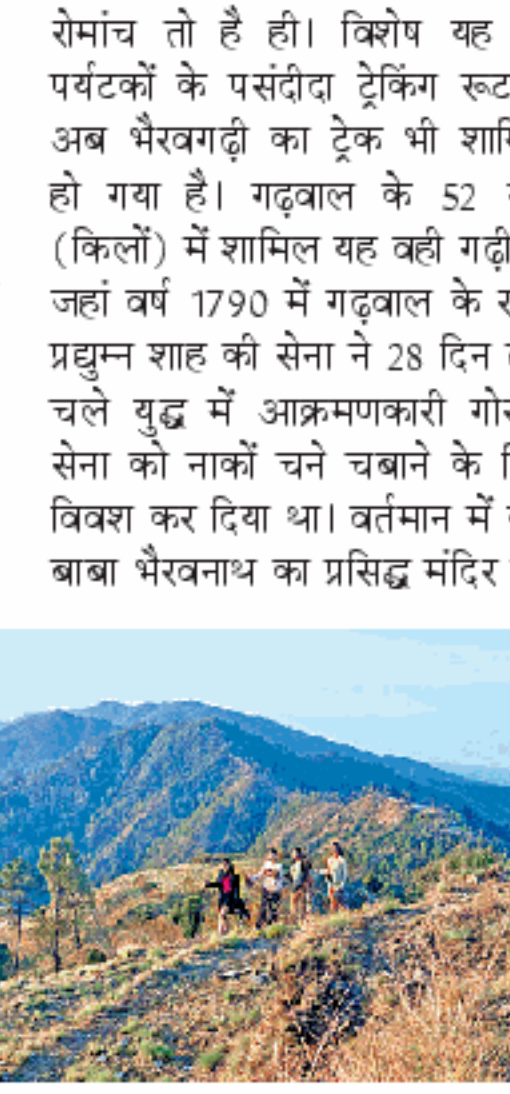


अजुन खंडेलवाल ● जगदगण

लैंसडौन: आप पर्यटन नगरी लैंसडौन (कालींडांडा) घूमने आए हैं और ट्रेकिंग के शौकीन हैं तो आसपास के नौ प्रमुख ट्रेक रूट स्वगत को तैयार हैं। बांज, बुरांश और चीड़ के जंगल की शीतल छांव के बीच से गुजरने वाले चार से लेकर 30 किमी तक लंबे ये ट्रेक स्वयं में अद्भुत रोमांच समेटे हुए हैं।

होटल भी करवा रहे ट्रेकिंग

पर्यटन नगरी में कई होटलों की ओर से भी पर्यटकों को ट्रेकिंग करवाई जाती है। इन होटलों की ओर से पर्यटकों को लिए जाने वाले प्लान में बाकायदा ट्रेकिंग को भी शामिल किया जाता है। इन होटलों के कर्मचारी ट्रेकिंग के इच्छुक पर्यटकों का दल बनाकर सुबह के समय उन्हें पैदल सैर कराते हैं। पर्यटक भी छोटे-बड़े ट्रेक रूट से गुजरकर आनंद की अनुभूति करते हैं। बीते वर्षों के दौरान ट्रेकिंग करने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, इसलिए होटलों की ओर से वीकेंड के अलावा गर्मियों के सीजन में भी इसे निरंतर जारी रखा जाता है।



भैरवगढ़ी ट्रेक से गुजरते पर्यटक ● जगदगण आकईव

लैंसडौन क्षेत्र के प्रमुख ट्रेकिंग रूट

- लैंसडौन एसबीआइ से राठी प्वाइंट होते हुए डेरियारखाल तक : पांच किमी
- कैंट कार्यालय के निकट चर्च रोड से झारापानी हवाघर होते हुए जयहरीखाल तक : सात किमी
- टिप-इन-टाप से संतोषी माता मंदिर होते हुए झारापानी व हवाघर तक : चार किमी
- जयहरीखाल मार्ग पर हवाघर के निकट केंद्रीय विद्यालय से भुल्ला ताल होते हुए सयर बाजार तक : आठ किमी
- लैंसडौन सदर बाजार-कोर्ट रोड-झिंगी लाइन-धुरा-फतेहपुर ट्रेक : 16 किमी
- लैंसडौन-जयहरीखाल-गुमखाल-कीर्तिखाल-भैरवगढ़ी ट्रेक : 18 किमी
- लैंसडौन- डेरियारखाल-चुंडई-मधुगंगेश्वर ट्रेक : 20 किमी
- लैंसडौन- डेरियारखाल-चुंडई-सिसलई-घोनीखाल-अधारियारखाल-चखुलियारखाल-ताइकेश्वर ट्रेक : 30 किमी
- चखुलियारखाल-गुंडलखेत-रजगगढ़ी ट्रेक : 10 किमी

बिज़नेस स्टैंडर्ड

वर्ष 18 अंक 107

सुनियोजित कदम से बनेगा उन्नति प्रदेश

सुनियोजित कदम से बनेगा उन्नति प्रदेश

सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) भारत के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एमएसएमई स्थानीय स्तर पर रोजिगार के अवसर सृजित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। देश से वस्तुओं के कुल निर्यात में एमएसएमई खंड की हिस्सेदारी 45 फीसदी से अधिक है और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इनका योगदान लगभग 30 फीसदी है। देश में इलेक्ट्रॉनिकी एवं सेमीकंडक्टर जैसे मूल्यवान क्षेत्रों सहित बड़े औद्योगिक संकुलों को जिस तरह महत्त्व दिया जा रहा है उतना ही ध्यान एमएसएमई के विकास के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करने पर दिया जाना चाहिए। इस दिशा में उत्तर प्रदेश सुनियोजित रूप से कदम बढ़ाता प्रतीत हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई की संख्या देश में सर्वाधिक है। राज्य में कुछ समय पहले विशेष रूप से एमएसएमई के लिए 11 जिलों में 15 औद्योगिक क्षेत्र तैयार करने से जुड़ी घोषणाएं हुई हैं। इनमें यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण भी शामिल है। राज्य में नए एमएसएमई के लिए 500 एकड़ जमीन का इंतजाम किया गया है। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के ये प्रयास सही दिशा में हैं। एमएसएमई विभाग द्वारा तैयार मसौदा योजना के अनुसार इन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 764.31 एकड़ जमीन आवंटित की जाएगी।

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 60 फीसदी है और राज्य के निर्यात में भी इसकी हिस्सेदारी 46 फीसदी तक पहुंच जाती है। राज्य की ऐसी इकाइयों की हिस्सेदारी देश के कुल एमएसएमई में लगभग 14 फीसदी है। एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) जैसी विशेष योजनाएं परंपरागत एवं कारीगरी कौशल को नए सिरे से बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ओडीओपी योजना के माध्यम से परंपरागत एवं कारीगरी कौशल आधुनिक मूल्य श्रृंखला से जुड़ रहा है। राज्य ने भौगोलिक संकेतकों (जीआई) के मामले में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। देश में सर्वाधिक जीआई टैग के साथ उत्तर प्रदेश स्थानीय उत्पादों के दम पर एक नया एवं विशिष्ट बाजार तैयार करने में सफल रहा है। वर्ष 2023-24 में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 13 फीसदी रही जो प्रदेश के राज्य सकल घरेलू उत्पाद (एसजीडीपी) दर 7.5 फीसदी से आगे निकल गई। वर्तमान मूल्यों पर विनिर्माण राज्य की अर्थव्यवस्था में 27 फीसदी योगदान दे रहा है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि राज्य के लगभग सभी जिलों में निवेश बढ़ रहा है। यह प्रगति एमएसएमई क्षेत्र को आगे बढ़ने में मदद करती है और एक संतुलित औद्योगिक तंत्र विकसित करने में भी सहायता मिली है।

ये सभी प्रयास उपयुक्त दशा में आगे बढ़ते दिख रहे हैं किंतु अब भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है। महिला उद्यमिता की कमी सबसे अहम बिंदु है जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य में मौजूद कुल एमएसएमई में महिलाओं द्वारा संचालित एमएसएमई की हिस्सेदारी मात्र 33 फीसदी है। यह अनुपात कई राज्यों की तुलना में कम है। लक्षित कौशल विकास, वित्त की उपलब्धता और महिला केंद्रित औद्योगिक संकुल रोजगार एवं उत्पादन और बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं।

उत्तर प्रदेश की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था चुनौती और अवसर दोनों पेश कर रही है। कृषि-प्रसंस्करण, खाद्य संरक्षण, ग्रामीण शिल्प और कृषि उपकरण विनिर्माण खंडों में अपार संभावनाएं हैं जिनका पर्याप्त लाभ नहीं उठाया गया है। इन खंडों में आगे बढ़ने की काफी गुंजाइश मौजूद है। उदाहरण के लिए राज्य की खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक नीति 2022-27 में इस बात का उल्लेख है कि राज्य की 24,000 खाद्य-प्रसंस्करण इकाइयों में केवल 6 फीसदी ही ऐसी हैं जिनका सालाना राजस्व 20 करोड़ रुपये से अधिक है। यह स्थिति क्षमता एवं कारोबार विस्तार की संभावनाएं उपलब्ध होने का संकेत दे रही है। कृषि क्षेत्र को एमएसएमई से जोड़ने वाली मूल्य श्रृंखला मजबूत बनाने से किसानों की आय बढ़ सकती है और ग्रामीण क्षेत्र में संकट भी कम हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि एमएसएमई नीतियां केवल अवसरचनra एवं भूमि पर ही केंद्रित न रहें बल्कि नियम अनुपालन का बोझ घटाने, वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने और ढुलाई से जुड़ी बाधाएं भी दूर करने में योगदान दें। देश के सबसे बड़े राज्य में अधिक औद्योगिक उत्पादन एवं रोजगार के अवसर भारत की संपूर्ण आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं में सुधार करेंगे।

आपका पक्ष

फास्टैग के सालाना पास के दिशानिर्देश तय हो

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में फास्टैग के सालाना पास योजना की घोषणा की। इससे निश्चित रूप से नियमित यात्रा करने वाले वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। इस साल 15 अगस्त से लागू होने जा रही इस योजना के तहत 3,000 रुपये के भुगतान पर एक वर्ष या 200 यात्राओं (जो पहले हो) तक देश के किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्बांध यात्रा की सुविधा मिलेगी। इससे न केवल टोल पर रुकावटें कम होंगी, बल्कि समय और ईंधन की भी बचत होगी। मगर इस पहल के कई ऐसे पक्ष हैं, जिन्हें स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है। सबसे प्रमुख सवाल यह है कि क्या यह सुविधा केवल राष्ट्रीय राजमार्गों तक सीमित रहेगी या राज्य और निजी टोल सड़कों पर भी लागू होगी। देश में अनेक टोल प्लाजा ऐसे हैं जो राज्य सरकारों या निजी कंपनियों द्वारा संचालित किए जाते हैं और वे भी फास्टैग का उपयोग करते हैं। ऐसे में



केंद्र सरकार ने बीते दिनों 3,000 रुपये के सालाना फास्टैग पास की घोषणा की, जिससे वाहन मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है

यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इस वार्षिक पास का उपयोग वहां किया जा सकेगा या नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ' 200 यात्राओं' की गिनती किस तरह होगी ? क्या एक टोल प्लाजा पर एक बार प्रवेश और

निकास को एक यात्रा माना जाएगा या दो बार गिनती होगी ? साथ ही, एक से अधिक टोल प्लाजा पार करने पर यात्राओं की गणना कैसे होगी, यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।



विश्वसनीय कार्बन बाजार बनाने में चुनौतियां अपार

कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य योजना में उत्तरदायी बाध्यकारी क्षेत्रों के दायरे को सीमित करने से न केवल बाजार का आकार छोटा होगा बल्कि इससे नकदी पर भी इसका असर पड़ेगा। बता रहे हैं अजय त्यागी

भारत सरकार ने जून 2023 में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) की अधिसूचना जारी की थी और उसके बाद से कई कदम उठाए गए ताकि इसको अमलीजामा पहनाया जा सके। उम्मीद है कि ट्रेडिंग 2026 में शुरू हो जाएगी और वर्ष 2027 तक इसका एक स्थिर बाजार हो जाएगा।

इस लेख में हम कार्बन बाजार बनाने के लिए सरकार के तरीकों का विश्लेषण और इसे एक सफल पहल बनाने में आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर बात करेंगे। इसे स्वीकारने में जरा भी संदेह नहीं है कि यह एक जटिल विषय है जिसमें लगातार बदलाव हो रहे हैं। निश्चित रूप से आगे कई अतिरिक्त मुद्दों पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी। पहले कुछ बुनियादी बातों से शुरुआत करते हैं। किसी भी वस्तु के बाजार के विकास के लिए वास्तविक और उचित अनुमानित मांग आवश्यक होती है। इसके बाद आपूर्तिकर्ता इसमें जुड़ते हैं और वे अपनी मांग और मूल्य का अनुमान लगाते हैं और साथ ही उस मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं। यही बातें कार्बन बाजार पर भी लागू होती हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओएफएण्डसीसी) ने हाल ही में कुछ क्षेत्रों में चिन्हित संस्थाओं के लिए कार्बन उत्सर्जन तीव्रता के लक्ष्य

विनय सिन्हा

शायद इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि यह पहले से ही प्रदर्शन करने, लक्ष्य हासिल करने और ट्रेडिंग की योजना (पीएटी) के तहत आता है। लेकिन यह गलत धारणा है कि ऊर्जा दक्षता में सुधार से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी जरूर आएगी। इसके अलावा, एक ही लक्ष्य के लिए दो योजनाएं चलाना भी समस्या खड़ी करता है। पीएटी योजना पर आगे बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझा जा सकता है और योजना में उत्तरदायी बाध्यकारी क्षेत्रों के दायरे को सीमित करने से न केवल बाजार का आकार छोटा होगा बल्कि तरलता पर भी इसका असर पड़ेगा।

कंपनियों के लिए उनके पिछले उत्सर्जन के आधार पर लक्ष्य तय करना गलत है। यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की महत्वाकांक्षा में कमी को दर्शाता है और इससे कार्बन क्रेडिट की पर्याप्त मांग बढ़ने की संभावना नहीं है। अहम सवाल यह भी है कि जिन कंपनियों के उत्सर्जन का पिछला रिकॉर्ड खराब रहा है, उन्हें ढील क्यों दी जाए ? सही तरीका यह होगा कि एक ही क्षेत्र में एक जैसी कंपनियों को (उदाहरण के तौर पर उत्पादन क्षमता के आधार पर) वर्गीकृत किया जाए और उन सभी के लिए एक ही लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। इससे एक बेंचमार्क तैयार किया जा सकेगा और उद्योग को संसाधनों का कुशलता से उपयोग करने, बेहतर तकनीक अपनाने और सही ईंधन का चुनाव करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा और तभी एक कार्बन बाजार तैयार हो पाएगा। सीसीटीएस ने गैर-बाध्यकारी संस्थाओं को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग में शामिल करने के लिए एक ‘ऑफसेट प्रणाली’ भी बनाई है। हालांकि, यूरोपीय संघ (ईयू)-एग्मिशन ट्रेडिंग स्कीम्स (ईटीएस) सहित दुनिया भर की उत्सर्जन ट्रेडिंग योजनाओं के अनुभव से अंदाजा होता है कि स्वेच्छिक भागीदारी से कार्बन लीकेज हो सकता है और डेटा की विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है और इसके कारण योजना की साख ही खतरे में पड़ सकती है।

अहम बात यह है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को शुरुआत में ही उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य तय करते हुए उन खराब सत्यापन जैसी गंभीर समस्याओं से जिनसे सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलता है और इसके बाद अन्य क्षेत्रों की जिम्मेदार कंपनियों को इस दायरे में लाना चाहिए।

सबसे अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करने वाले उद्योगों में स्टील क्षेत्र को शामिल क्यों नहीं किया गया, यह बात भी समझ से परे है। इसी तरह, ताप ऊर्जा क्षेत्र जिसका कार्बन फुटप्रिंट सबसे अधिक है, उसे

नीतीश कुमार टीम के एक बहुमूल्य सदस्य

बिहार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक दलित विधायक के साथ हाल ही में हुई बातचीत में राज्य में आगामी विधान सभा चुनाव के बारे में नई सच्चाई सामने आई। समस्तीपुर क्षेत्र के विधायक एक गणितज्ञ हैं, वह पंचायत और बाद में 2020 के विधान सभा चुनाव लड़ने के लिए भाजपा द्वारा उनकी सेवाएं मांगे जाने तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में पूर्णकालिक प्रचारक भी थे। वह भाजपा में एक प्रभावशाली दलित आवाज हैं। उन्होंने बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में कहा, ‘हम वास्तव में नीतीश जी का सम्मान करते हैं, न केवल सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए, बल्कि उनके जीने के तरीके के लिए भी। उनका कोई परिवार नहीं है। पिछले इन सभी वर्षों में, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। उनके पास जो कुछ भी था, उन्होंने बिहार को दिया है। इस हिसाब से वह उन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमें आरएसएस में सिखाए गए हैं।’ नीतीश चुनावों में अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का नेतृत्व कर रहे हैं और यह उनका आखिरी चुनाव हो सकता है।

लेकिन अब उनकी गिरगिट जैसी राजनीति और प्रशासन पर ढीली पकड़ के बारे में ताने सुनने को मिलते हैं। एक समय ऐसा भी था जब नीतीश कुमार ने राज्य में भाजपा को हिलाकर रख दिया था। बहुत लोगों को याद होगा कि जब 2006 में राजग ने घोषणा की थी कि सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य

किया जाना चाहिए, नीतीश ने बिहार में इसे लागू करने से इनकार कर दिया, जबकि जेडीयू राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का हिस्सा थी। जून 2010 में पटना में आयोजित भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान, स्थानीय दैनिकों में पूरे पेज का विज्ञापन छपा जिसमें नीतीश कुमार ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को

बाद राहत सहायता के रूप में 5 करोड़ रुपये देने के लिए धन्यवाद दिया।

लेकिन बिहार को भिखारी के रूप में चित्रित करने से नाराज नीतीश कुमार ने भाजपा नेताओं के लिए आयोजित रात्रिभोज को रद्द कर दिया। नीतीश कुमार ने गुजरात सरकार को 5 करोड़ रुपये भी लौटा दिए। इसके बाद जून 2013 में गोवा में मोदी को भाजपा के 2014 के लोक सभा चुनाव अभियान समिति का प्रमुख नियुक्त किए जाने के तुरंत बाद जदयू ने भाजपा के नेतृत्व वाले राजग के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया। अब वे फिर से दोस्त हैं, हालांकि भाजपा जदयू में होने वाले कदमों, खासकर उत्तराधिकार पर सावधानीपूर्वक नजर रख रही है। भाजपा के लिए यह जरूरी है कि जदयू का एक इकाई के रूप में अस्तित्व रहे। बिहार के अत्यंत पिछड़े वर्ग (ईबीसी) और कुर्मी व कोइरी जातियां अभी भी नीतीश कुमार के पीछे मजबूती से खड़ी हैं।



सियासी हलचल

आदिति फडणीस

के मंगनी लाल मंडल को राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) का अध्यक्ष नियुक्त करना इसी हिसाब का रणनीतिक कदम है। भाजपा के आकलन के अनुसार, इस चुनाव में हिंदुत्व को पीछे रखना ही बेहतर है। निश्चित रूप से पार्टी बालादेशी घुसपैठ के मुद्दों को उठाएगी, खासकर किशनगंज जैसे इलाकों में जहां 65 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है।

चाहिए, जिन्हें मजबूत निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन तंत्र के साथ-साथ सख्त नियमों के दायरे में रखा गया हो। जानकारी के मुताबिक, ईयू-ईटीएस में ऑफसेट प्रणाली पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब बात करते हैं मौजूदा पीएटी योजना और सीसीटीएस के महत्त्वपूर्ण जुड़ाव के मुद्दे पर। सीसीटीएस काफी हद तक पीएटी योजना पर आधारित है, जिसे 2012 से ही ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) एक बाजार तंत्र के रूप में नियमों के दायरे में आने वाली संस्थाओं में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए संचालित कर रहा है। हालांकि इस तरीके के कुछ अपने निहितार्थ हैं।

सवाल यह भी है कि क्या सीसीटीएस में शामिल क्षेत्रों को कवर करने वाली पीएटी योजना समानांतर रूप से जारी रहेगी ? पीएटी चक्र 8 को वर्ष 2025-26 के लिए पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है, ऐसे में यह सह-अस्तित्व कैसे काम करेगा ? बाजार को क्यों विभाजित किया जाए ? इसके बजाय, सीधे उत्सर्जन तीव्रता को लक्षित करने वाली केवल सीसीटीएस ही क्यों न हो ? पीएटी योजना की पहले भी आलोचना हुई है, जिसमें ढीले लक्ष्य तय करना, बाजार में ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र (ईएससीईआरटी) की अत्यधिक आपूर्ति के कारण प्रमाण पत्र की कीमतों में कमी, असंतोषजनक क्रियान्वयन और खराब तरीके का अमल शामिल है।

ऐसा लगता है कि पीएटी 3 चक्र के बाद से, विभिन्न चरणों को बंद करने के लिए आवश्यक कदम अब भी लंबित हैं। याद रहे कि पीएटी 3 चक्र, वर्ष 2017-2020 की अवधि के लिए था और इसके बाद पीएटी 4 से पीएटी 8 तक के चक्रों को अधिसूचित किया गया है। क्या इन चरणों में शामिल बाध्यकारी संस्थाओं को सीसीटीएस के तहत तभी अनुमति मिलेगी जब ये चरण बंद हो जाएंगे ? पीएटी के तहत बकाया ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र को सीसीटीएस के तहत कार्बन क्रेडिट में बदलने की प्रणाली क्या होगी ? पीएटी व्यवस्था के तहत प्रचलित खराब निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन प्रक्रियाओं को देखते हुए इनकी आखिर विश्वसनीयता क्या है ? क्या इन्हें सामान्य कार्बन क्रेडिट माना जाएगा या उन के लिए एक अलग वर्गीकरण या एक्सचेंज पर एक अलग ट्रेडिंग सेगमेंट होगा ? देश में एक मजबूत और विश्वसनीय कार्बन बाजार बनाने के लिए इन सभी मुद्दों पर ठीक से विश्लेश और समाधान की आवश्यकता है। (*लेखक ऑज्ज्वर रिसर्च फाउंडेशन में विशिष्ट फेलो हैं और सेबी चेयरमैन रह चुके हैं*)

लेकिन धार्मिक मुद्दों पर विवाद खड़ा करने का यह

सही समय नहीं है, क्योंकि नीतीश के साथ गठबंधन ने राजग को मुस्लिम समर्थन दिलाया है, भले ही छोटा हो। इसके बजाय, शासन और राज्य में प्रशासनिक क्षमता बनाने के लिए लगातार सरकारों, खासकर अपने पहले कार्यकाल में नीतीश कुमार के प्रयासों को लेकर अपील होगी। उदाहरण के लिए यह कोई संयोग नहीं है कि बिहार में पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब भारत में सबसे अधिक (24 फीसदी) है और 2022 से 2024 के बीच ही यह 2 फीसदी बढ़ गया है। यह आंशिक रूप से नीतीश कुमार द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले (2005-2014) और दूसरे (2015-2020) कार्यकाल में लड़कियों की शिक्षा में किए गए निवेश का परिणाम है। पार्टी का मानना ​​है कि शराबबंदी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है और जो लोग इसके खिलाफ तर्क देते हैं, जिनमें आरके सिंह जैसे पार्टी के पूर्व सांसद भी शामिल हैं, वे जमीनी हकीकत को नहीं समझते हैं। शराबबंदी को लागू करने में तमाम खामियों और खामियों के बावजूद, भाजपा का मानना ​​है कि सिर्फ इसी मुद्दे पर महिलाओं का वोट जाति से ऊपर है। पलायन को रोकने के क्षे्र मिथिलांचल के विकास जैसे क्षेत्रीय मुद्दों को भी बिहार में विकास के मुद्दे के रूप में तैयार किया जाएगा।

अगर मोदी-कुमार के संयुक्त प्रयास से भाजपा को भारी लाभ होता है लेकिन जेडीयू को नहीं, तो क्या नीतीश कुमार को समीकरण से पूरी तरह बाहर किया जा सकता है ? इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसा कॉरपोरेट भाषा में कहा जाता है, फिलहाल ‘नीतीश कुमार टीम के एक बहुमूल्य सदस्य है।’

देश-दुनिया



फोटो – पीटीआई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को 67 वर्ष की हो गईं । शुक्रवार को उन्होंने उत्तराखंड में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के एक संस्थान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी नीतियां दिव्यांग लोगों को सशक्त बनाने और उन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करने के लिए बनाई गई हैं।

विनोद जोहरी, दिल्ली

छोटे अपराध पर दोषी को साफ करने होंगे सड़क-पार्क

फैसला

■ गौरव त्यागी

नई दिल्ली। राजधानी में पहली बार छोटे अपराधों में दोषी पाए जाने पर अस्पताल के वाडों, सड़कों और पार्कों में सफाई की सजा मिल सकती है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने ‘कम्युनिटी सर्विस’ यानी समाज सेवा से जुड़ी 12 प्रकार की सेवाओं को पहली बार अधिसूचित किया है। हालांकि, यह सजा क्या होगी इसे तय करने का अधिकार पूरी तरह से कोर्टों के पास होगा। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, जो 12 कम्युनिटी सर्विस को सजा के तौर पर



रखा गया है वह एक दिन से लेकर 31 दिन तक या 40 से 240 घंटे तक हो सकती है। सरकार के मुताबिक, दिल्ली उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर सजा तय

इसमें हो सकती समाज सेवा की सजा

गृह विभाग के अधिकारियों के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत जुलाई 2024 से कम्युनिटी सर्विस को दंड के रूप में शामिल किया गया है। आत्महत्या का प्रयास (धारा 226), सरकारी कर्मचारी द्वारा अवैध व्यापार (धारा 202), पेशी से गैर-हाजिरी (धारा 209), पांच हजार रुपये से कम की चोरी (धारा 303(2)), सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर उपद्रव करना (धारा 355), मानहानि (धारा 356(2) समेत अन्य अपराध शामिल है।

की गई है, लेकिन ये तय करने का मकसद अदालतों की विवेकाधिकार को सीमित करना नहीं है। ये सेवाएं भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) की धारा 4 (एफ) के

ये है समाज सेवा वाली 12 सजाएं

- अस्पतालों के वाडों और आसपास की सफाई
- सड़कों के किनारे धास काटना
- सार्वजनिक पार्कों की सफाई
- पुस्तकालयों में किताबें व्यवस्थित करना और बाइंडिंग करना
- सरकारी स्कूलों में रंगाई-पुताई आदि में सहयोग

- वृद्धाश्रमों, अनाथालयों में सेवा
- सड़क किनारे पौधरोपण
- सामुदायिक रसोई में सहयोग
- ट्रैफिक नियमों के पालन में पुलिस सहायता
- जल वितरण केंद्रों पर सहयोग
- सरकारी भवनों की सफाई
- सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहायता

कदम न्यायिक सुधार और पुनर्वासितामक न्याय प्रणाली की दिशा में बड़ा कदम है, जिससे न केवल अपराधियों का पुनर्वास हो सकेगा, बल्कि समाज को भी लाभ मिलेगा।

कैदियों की चित्रकला की प्रदर्शनी लगेगी

नई दिल्ली, व.सं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने गुरुवार को तिहाड़ जेल का दौरा किया। उन्होंने तिहाड़ प्रशासन के साथ मिलकर गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति में कार्यक्रम करने की इच्छा जताई है।

साढ़े चार गुना ज्यादा होता है प्रदूषण

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के मुताबिक पुराने वाहनों में ज्यादातर बीएस छह मानकों से नीचे के इंजन वाले हैं। इन पुराने इंजनों में उत्सर्जन अधिक होता है। बीएस छह वाहन की तुलना में बीएस चार वाहनों में साढ़े चार गुना ज्यादा उत्सर्जन होता है। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पुराने वाहनों की भारी संख्या को देखते हुए यह उत्सर्जन काफी ज्यादा है।

दोपहिया वाहनों की संख्या भी कम नहीं

पुराने वाहनों में कार्रवाई को लेकर आमतौर पर चार पहिया वाहनों पर ही ध्यान केंद्रित रहता है। लेकिन, आयोग के मुताबिक दोपहिया वाहनों की संख्या भी कम नहीं है। दिल्ली में लगभग 62 लाख वाहन हैं जो अपनी समस्याधि पूरी कर चुके हैं। इनमें से 41 लाख के लगभग वाहन दोपहिया वाहन हैं।

दिल्ली में प्रवेश रोकने की भी योजना

आयोग ने बताया कि ऐसे ही एएनपीआर कैमरे दिल्ली के सभी 126 प्रवेश बिंदुओं पर भी लगाने की योजना है। इसके जरिए पुराने वाहनों की पहचान दिल्ली की सीमा पर ही कर ली जाएगी और उन्हें बाहर से ही लौटाया जा सकेगा।

निगम ने अवैध पार्किंग को हटाया

नई दिल्ली, व.सं। दिल्ली नगर निगम के शाहदरा उत्तरी जोन में शुक्रवार को अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई हुई। जोन के सोनिया विहार वार्ड में अवैध पार्किंग को हटाया गया और चार वाहनों को जब्त किया।

इस दौरान 68 गाड़ियों के चालान काटे गए। इस कार्रवाई में शाहदरा उत्तरी जोन के सामान्य ब्रांच, रखरखाव विभाग ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई की। अधिकारियों ने बताया कि जोन में अवैध पार्किंग और अतिक्रमण की कई शिकायतें प्राप्त हुईं। जिसके बाद कार्रवाई की गई।

कैदियों की चित्रकला की प्रदर्शनी लगेगी

नई दिल्ली, व.सं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने गुरुवार को तिहाड़ जेल का दौरा किया। उन्होंने तिहाड़ प्रशासन के साथ मिलकर गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति में कार्यक्रम करने की इच्छा जताई है।

गोयल ने इस दौरान जेल के महानिदेशक (कारागार) सतीश गोलचला से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि समिति कैदियों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाएगी। साथ ही, कैदियों द्वारा बनाए गए हैंडीबैम्स, लकड़ी का सामान, बैग सहित कई उत्पादों के लिए गांधी दर्शन में एक दुकान आर्वाइट करेगी। यहां इन वस्तुओं की बिक्री भी होगी।

डेंगू और मलेरिया के प्रति जागरूक किया

नई दिल्ली, व.सं.। दिल्ली नगर निगम के मुखर्जी नगर वार्ड में शुक्रवार को मच्छर जनित बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान की शुरुआत हुई।

इस अभियान को निगम के सिविल लाइंस जोन के जीटीबी नगर में शुरू किया गया। इस अवसर पर महापौर राजा इकबाल सिंह, निगम अधिकारी और स्थानीय निवासी शामिल हुए। महापौर ने आरडब्ल्यूए सदस्यों और स्थानीय लोगों से अपील की कि वे मच्छर नियंत्रण के लिए सक्रिय रूप से सहयोग करें।

शहर 30 S

जलभराव पर बहाना नहीं चलेगा: आप

नई दिल्ली। दिल्ली में जलभराव को लेकर आप ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सीरभ भास्कराज ने जल निकासी व्यवस्था के ध्वस्त का आरोप लगाते हुए कहा कि आज दिल्ली का हर नाला भाजपा शासित एजेंसियों के अधीन है। ऐसे में उनका कोई बहाना नहीं चलेगा।



मद्रासी कैप के सैकड़ों परिवारों को राशन बांटा

नई दिल्ली। जंगपुरा स्थित मद्रासी कैप में एक जून को अदालत के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, जिसमें करीब 370 झुग्गियां ध्वस्त की गईं। कार्रवाई के बाद करीब 350 परिवार बेघर हो गए थे। तमिलनाडु सरकार ने इनमें से 250 से अधिक पीड़ित परिवारों को चाणव्यपुरी स्थित तमिलनाडु हाउस में राशन और आर्थिक मदद दी है। पीड़ितों को बसों से तमिलनाडु हाउस लाया गया।

‘अस्पतालों पर सरकार का दावा फेल’

नई दिल्ली। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार के 100 दिनों के सफल होने का दावा फेल साबित हुआ है। इसी के चलते सरकारी अस्पतालों की बदहाली पर उप राज्यपाल द्वारा चिंता जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पिछले 10 वर्षों से बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगातार आवाज उठा रही है।

मद्रासी कैप के सैकड़ों परिवारों को राशन बांटा

नई दिल्ली। जंगपुरा स्थित मद्रासी कैप में एक जून को अदालत के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, जिसमें करीब 370 झुग्गियां ध्वस्त की गईं। कार्रवाई के बाद करीब 350 परिवार बेघर हो गए थे। तमिलनाडु सरकार ने इनमें से 250 से अधिक पीड़ित परिवारों को चाणव्यपुरी स्थित तमिलनाडु हाउस में राशन और आर्थिक मदद दी है। पीड़ितों को बसों से तमिलनाडु हाउस लाया गया।

विधानसभा को विरासत केंद्र में बदलने का समर्थन

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा को विरासत केंद्र के रूप में रूपांतरित किए जाने के प्रयासों को केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत का समर्थन मिला है। विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता को संबोधित पत्र में शेखावत ने लिखा है कि हम आपके साथ मिलकर इसे संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।



आईपीयू के एमबीए में दस तक आवेदन का मौका

नई दिल्ली। आईपी यूनिवर्सिटी के लेटरल एंट्री टू एमबीए (फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी) में दस जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक इस प्रोग्राम में आवेदन के लिए आवेदक के पास फायर एंड सेफ्टी में एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। प्रोग्राम में दाखिले आवेदक के पीजी डिप्लोमा के प्राप्तांक के आधार पर होंगे।

फीस वृद्धि के विरोध में अभिभावक प्रदर्शन करेंगे

नई दिल्ली। राजधानी के निजी स्कूलों में फीस वृद्धि और छात्रों के साथ भेदभाव का मामला थम नहीं रहा है। अब अभिभावक अपना विरोध जताने के लिए सड़कों पर आने को मजबूर हो गए हैं। अभिभावकों ने शनिवार को सीएम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। यूनाइटेड पेरेंट्स वॉइज के बैनर के तले यह प्रदर्शन किया जाएगा।

कनॉट प्लेस में 25 को इमरजेंसी पर प्रदर्शन

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने इस बार 1975 के आपातकाल को लोकतंत्र के काले अस्थाय के रूप में प्रचारित करने का फैसला किया है। कला, संस्कृति, भाषा एवं पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने 25 जून को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में आपातकाल की पुष्टयुग्मि पर विरोध प्रदर्शनी आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदर्शनी सुबह 10 बजे शुरू होगी।

दिल्ली जैसे शहर में रहना बहुत महंगा : हाई कोर्ट

■ हेमलता कौशिक

■ **कोर्ट ने हादसे में व्यक्ति की मौत के बाद पीड़ित परिवार का मुआवजा बढ़ाने के आदेश दिए**

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी के महंगे खर्चों का हकाला देते हुए एक परिवार का मुआवजा बढ़ाने के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली बहुत महंगा शहर है। यहां पीड़ित परिवार (जिसमें तीन सदस्य हैं) महज तीन लाख रुपये का मुआवजा देना पर्याप्त नहीं है। इसलिए परिवार को से मुआवजा बढ़ाने के लिए दावा डाला।

को उच्च न्यायालय का रुख करना पड़ा। हालांकि पीठ ने इस पर दुख जताया कि मुआवजा बढ़ाने का निर्णय सात साल बाद लिया गया। परन्तु साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि परिवार ने देरी से मुआवजा बढ़ाने के लिए दावा डाला।

अज्ञात वाहन ने मारी थी टक्कर : एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले हरी चंद को वजीराबाद के पास 15 अगस्त 2018 को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में हरी चंद गंभीर रूप से जखमी हुआ था। 26 अक्टूबर 2018 को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। यह मामला तीस हजारी स्थित वाहन दुर्घटना मुआवजा दावा पंचाट ने समझ आया। तीस हजारी अदालत ने 27 फरवरी 2019 को परिवार की हालात को देखते हुए दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना के तहत मुआवजा देने की सिफारिश की थी।

को उच्च न्यायालय का रुख करना पड़ा। हालांकि पीठ ने इस पर दुख जताया कि मुआवजा बढ़ाने का निर्णय सात साल बाद लिया गया। परन्तु साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि परिवार ने देरी से मुआवजा बढ़ाने के लिए दावा डाला।

अज्ञात वाहन ने मारी थी टक्कर : एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले हरी चंद को वजीराबाद के पास 15 अगस्त 2018 को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में हरी चंद गंभीर रूप से जखमी हुआ था। 26 अक्टूबर 2018 को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। यह मामला तीस हजारी स्थित वाहन दुर्घटना मुआवजा दावा पंचाट ने समझ आया। तीस हजारी अदालत ने 27 फरवरी 2019 को परिवार की हालात को देखते हुए दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना के तहत मुआवजा देने की सिफारिश की थी।

करंट लगने से कर्मचारी की मौत

नई दिल्ली, प्र.सं.। मजनुं का टीला स्थित जल शोधक संयंत्र में शुक्रवार दोपहर को काम करने के दौरान कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 25 वर्षीय संजू के तौर पर हुई है।

सिविल लाइंस पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। सँजु परिवार सहित नोएडा के पास धौलपुर गांव में रहता था। फिलहाल चंद्रवाल जल शोधक संयंत्र में शुक्रवार को काम कर रहा था। इसी दौरान पानी में करंट आने से वह इसकी चपेट में आ गया। उसे संत परमानंद अस्पताल ले गए जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।



नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। बादल और हल्की बूँदाबांदी दिल्ली के लोगों को गर्मी से खासी राहत दी है। शुक्रवार को दिल्ली अधिकतम तापमान सामान्य से आठ डिग्री सेल्सियस तक कम रिकार्ड किया गया।

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले तीन दिनों के बीच हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली के कई हिस्सों में शुक्रवार को

इजरायल-ईरान से लाए जाएं गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप

नई दिल्ली, प्र.सं.। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेट्री (डीएसजीएमसी) ने इजरायल और ईरान में चल रहे युद्ध के बीच श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूपों को तत्काल भारत लाने की मांग की है। इसके साथ ही यह भी मांग की है कि दोनों देशों में फंसे तमाम भारतीय नागरिकों को भी स्वदेश सुरक्षित लाया जाए।

कमेटी के अध्यक्ष हरमती सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह कालहों ने विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर को पत्र लिखकर यह मांग उठाई है। पत्र में कहा गया कि दोनों देशों में सिख संगतों के पास मौजूद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूपों को पूरी मर्यादा के साथ नई दिल्ली लाना बेहद जरूरी है। कमेटी ने सरकार को इस पानव काम में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। साथ ही, इजरायल और ईरान में पढ़ाई, यात्रा या अन्य कारणों से गए सिखों और भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी की मांग की गई है।

यहां देखने को मिलते हैं 500 से ज्यादा वाद्ययंत्र

विश्व संगीत दिवस

■ अभिनव उपाध्याय

नई दिल्ली। 121 जून को दुनिया में विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। अगर आप भारतीय संगीत की समृद्ध विरासत को करीब से देखना और समझना चाहते हैं तो संगीत नाटक अकादमी की वाद्य यंत्र दीर्घा जरूर जाएं।

यह देश की उन खास सांस्कृतिक जगहों में से एक है, जहां भारतीय वाद्य यंत्रों को संरक्षित और प्रदर्शित किया गया है। यहां पर करीब 500 पारंपरिक वाद्य यंत्र मौजूद हैं। इनमें से कई अब दुर्लभ हो गए हैं। खास बात यह है कि यहां प्रसिद्ध तबला वादक किशन महाराज का



रविंद्र भवन स्थित संगीत नाटक अकादमी की संगीत वाद्ययंत्र दीर्घा में कई प्राचीन और दुर्लभ वाद्य यंत्र देख सकते हैं। ● संजु खेला

तबला भी रखा गया है। इसके अलावा रुद्र ढोणा और मयूरी ढोणा भी लोगों का ध्यान खींचती हैं। इस दीर्घा में वाद्य यंत्रों को चार

श्रेणियों में बांटा गया है :तत वाद्य (तार वाले वाद्य जैसे सितार) सुफिर वाद्य (फूंक वाले जैसे बांसुरी) अवनमद वाद्य (चमड़े पर आधारित जैसे तबला, धोलक) घन वाद्य (बजाने वाले जैसे मंजीरा)।

यहां सिर्फ शास्त्रीय वाद्य ही नहीं, बल्कि देश भर के लोक वाद्य यंत्र भी हैं। जैसे — चांग, नागफनी, सुरबहार, सुनारि, चकरा, मकरा ढोणा आदि। 1964 में मशहूर वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन ने इस दीर्घा का उद्घाटन किया था। 1968 में यहां पहली बड़ी प्रदर्शनी लगी थी। तब से इन वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी दुनिया के कई देशों में हो चुकी है। संगीत नाटक अकादमी के सचिव राजू दास बताते हैं कि यह दीर्घा सिर्फ प्रदर्शन के लिए नहीं है, बल्कि इसका मकसद भारतीय वाद्य परंपरा को जीवित रखना और नई पीढ़ी को इससे जोड़ना है।

सुरक्षा उपायों का रखा जाएगा विशेष ध्यान

अधिकारियों ने बताया कि हॉट एयर बैलून आम तौर पर 500 फीट से तीन हजार फीट तक की ऊंचाई तक उड़ान भरता है। इसमें सुरक्षा के सभी तरह के उपायों को ध्यान में रखते हुए राइड शुरू करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि लोगों को किफायती आधार पर प्रति व्यक्ति हॉट एयर बैलून की राइड की सेवा उपलब्ध हो। अभी जयपुर में हॉट एयर बैलून राइड के लिए प्रति व्यक्ति 12 हजार रुपये से 15 हजार रुपये का टिकट मिलता है। हमी शहर में 13 हजार रुपये से 25 हजार रुपये प्रति व्यक्ति टिकट मिलता है।



क्रिकेट का नया दौर

इंग्लैंड के हेडिंगले में भारतीय क्रिकेट टीम अपने नए कप्तान शुभमान गिल के नेतृत्व में टेस्ट खेलने उतरी और उसके साथ ही, भारतीय क्रिकेट के नए दौर का आगाज हो गया। करीब डेढ़ दशक से भारतीय टेस्ट क्रिकेट का चेहरा रहे विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन और मोहम्मद शमी के बिना उतरी टीम अधूरी सी लग रही है। टीम में जो बड़ा सुनापन पैदा हुआ है, उसे भरने की जिम्मेदारी नई टीम ईंडिया पर है। अगर हम पिछली टेस्ट टीम को देखें, तो उसके कुछ ही सदस्य इस नई टीम का हिस्सा हैं। वरिष्ठों में जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा, के एल राहुल और ऋषभ पंत पर सर्वाधिक दारोमदार होगा। कोई शक नहीं कि विराट कोहली की कमी मैदान पर खल रही है। जब विराट मैदान पर होते थे, तो अपनी चपलता से एक अलग ही रौनक बनाए रखते थे। खेर, हरेक खिलाड़ी का अपना वक्त होता है। कुछ भारतीय दिग्गजों का वक्त खत्म हुआ है, तो कुछ का शुरू हो रहा है, ऐसी ही उम्मीद भारतीय क्रिकेट के प्रेमी लगाए हुए हैं। विगत तीन दशक में भारतीय क्रिकेट का चेहरा बार-बार बदला है और नई प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। बड़े दिग्गज जाएंगे, तो युवाओं को मौका मिलेगा।

अक्सर देखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में खराब खेलकर खिलाड़ी विदा होते हैं और इंग्लैंड में अच्छा खेलकर उनके करियर का आगाज होता है। शायद फिर ऐसा ही होने वाला है। शुभमान गिल प्रतिभा के धनी कप्तान हैं। कप्तान के लिए जरूरी तमाम योग्यताओं से लैस गिल के पास मौका है कि वह आगे बढ़कर नेतृत्व करें और इंग्लैंड में भारतीय क्रिकेट की एक नई कहानी लिखें। भारतीय टीम को अभी पांच टेस्ट मैच खेलने हैं और वहां आम तौर पर हमारी टीम का इतिहास मुश्किल भरा रहा है। हेडिंग्वे, लीड्स में तो भारत टेस्ट जीत चुका है, लेकिन बर्मिंघम और मैनचेस्टर में भारत के लिए टेस्ट जीत दुर्लभ रही है। यह भी ध्यान रखने की बात है कि भारत केवल तीन बार ही इंग्लैंड में टेस्ट श्रृंखला जीत सका है। पिछली बार साल

2007 में भारत को वहां टेस्ट श्रृंखला में जीत मिली थी, तब राहुल द्रविड कप्तान थे। इंग्लैंड में तीन टेस्ट मैचों में जीत दिलाने वाले सफलतम कप्तान विराट कोहली भी वहां श्रृंखला विजय में नाकाम रहे। अतः शुभमान गिल के पास स्वर्णिम इतिहास लिखने का पूरा मौका है। संभलकर खेलते हुए युवाओं की टीम को जल्दी ही लय में आना होगा। ध्यान रहे, अब युवाओं को पहले की तरह ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे। आज देश में क्रिकेट प्रतिभाओं की भरमार है और बोर्ड टीम का एक मजबूत संयोजन प्राप्त करने तक बदलाव से नहीं चूकेगा।

महज 25 वर्षीय शुभमान गिल पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जो भरोसा जताया है, उस पर किसी भी दिग्गज क्रिकेट विशेषज्ञ ने प्रश्न नहीं किया है। शुभमान ने पांच साल पहले जब टेस्ट क्रिकेट में आगाज किया था, तभी से उनमें कप्तान की संभावना देखी जा रही थी। आज उनके सामने अच्छे खेल व सफल कप्तान होने की नई-पुरानी मिसालें बहुत हैं। इसी महाने दक्षिण अफ्रीका की टीम विश्व टेस्ट चैंपियन हुई है, जिसमें उनके कप्तान तेंबा बावुमा के योगदान को विशेष रूप से रेखांकित किया जा रहा है। प्रतिभा में शुभमान गिल से कमतर होने के बावजूद बावुमा ने मात्र तीन वर्ष की टेस्ट कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका को विश्व चैंपियन बना दिया। ठीक ऐसी ही उम्मीद क्रिकेट प्रेमियों को शुभमान से होगी। उन्हें भारतीय क्रिकेट के लिए शुभ सन्निहत होते हुए अपने नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट के नए दौर को अनछुई ऊंचाइयों तक ले जाना होगा।

हिन्दुस्तान 75 साल पहले 21 जून, 1950

रूस का भय

पश्चिमी राष्ट्र रूस से जितने भयभीत हैं, उतने और किसी वस्तु से नहीं। उनकी सारी योजनाएं रूसी खतरे को लक्ष्य में रखकर बन रही हैं। अमरीका के कर्णधार यह समझ बैठे हैं कि रूसी खतरे का मुकाबला केवल एक ही प्रकार से किया जा सकता है कि उसे शस्त्रास्त्रों के निर्माण और सैनिक तैयारियों में पछाड़ दिया जाये। अमरीका ने अणु बम का निर्माण किया और अब तक उसका खासा ढेर अपने पास जमा कर लिया होगा। अब यह उदजन बम (हाइड्रोजन बम) बनाने के लिए अपने विशाल साधनों का उपयोग कर रहा है। वाशिंगटन की एक खबर में कहा गया है कि अमरीकी प्रेसिडेंट श्री ट्रुमन अमरीकी कांग्रेस से उदजन बम निर्माण कार्य को गति देने के लिए 30 करोड़ डालर की रकम मंजूर करने का अनुरोध करेंगे। किन्तु दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, जो शस्त्र-निर्माण की इस प्रतिस्पद्धा को शांति का मार्ग नहीं मानते, बल्कि उनका यह खयाल है कि इससे तो एक और कर्षक युद्ध अनिवार्य हो जायेगा और वह दोनों लड़ाकू पक्षों को तबाह और बर्बाद कर देगा। ऐसे लोगों में जगत-प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा. आइन्स्टीन भी शामिल हैं। उन्होंने यह मान्यता प्रकट की है कि शस्त्र-निर्माण की प्रतिस्पद्धा खुले संघर्ष अथवा युद्ध को रोकने का निष्कृप्ततम तरीका है। यदि शस्त्र-निर्माण की यह प्रतिस्पद्धा जारी रखी तो युद्ध होकर रहेगा।

डा. आइन्स्टीन का मत केवल नकारात्मक नहीं है। उन्होंने शांति कायम रखने का जो उपाय सुझाया है, वह वही है जो महात्मा गांधी ने सुझाया था। महात्मा गांधी का सिद्धांत था कि बुराई के साथ असहयोग करो और डा. आइन्स्टीन कहते हैं कि शांति का मार्ग इसी सिद्धांत में निहित है। महात्मा गांधी के विचार हमारे जमाने के सभी राजनीतिज्ञों से अधिक प्रगतिशील थे और इसलिए डा. आइन्स्टीन चाहते हैं कि हमको गांधीजी की भावना के अनुसार काम करने की कोशिश करनी चाहिए। डा. आइन्स्टीन का प्रस्ताव कि तमाम राष्ट्र अपने अणु बमों, परमाणु बमों, उदजन बमों का सारा संग्रह एक सर्वोपरि विश्व सत्ता के हवाले कर दें। ऐसी विश्व सत्ता अभी अस्तित्व में आनी बाकी है। बड़े राष्ट्र जो करोड़ों रुपया अणु और उदजन बमों के निर्माण के पीछे खर्च रहे हैं, डा. आइन्स्टीन के प्रस्ताव को अव्यावहारिक कहकर विनोद में उड़ा देंगे, किन्तु दुनिया को अन्त में किसी ऐसे ही प्रस्ताव को स्वीकार करना होगा।

स्वस्थ जीवन का महान सूत्र है योग

प्रत्येक वर्ष 21 जून को ‘अंतरराष्ट्रीय योग दिवस’ मनाया जाता है। यह दिन केवल योग के महत्व को दर्शाने के लिए ही नहीं, बल्कि यह याद दिलाने के लिए भी है कि जीवनशैली में योग को अपनाकर हम दैहिक, मानसिक और भौतिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। इस दिन का विशेष कारण यह भी है कि यह उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे जीवन व ऊर्जा के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। आज के युग में प्रदूषण, रासायनिक तत्वों से भरा भोजन, माइक्रो प्लास्टिक का फैलाव और जीवन-शैली से जुड़ी बीमारियां मानव शरीर को लगातार नुकसान पहुंचा रही हैं। केवल दवाओं और वैक्सिन पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शरीर की प्राकृतिक योग प्रतिरोधक क्षमता ही हमें लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती है।

👉 **कूलदीप सिंह भाटी**, ब्लॉगर
सुरक्षित रख सकती है।

👉 **ऋषि सुभाष बुढ़ावन** वाला, टिप्पणीकार
भारत की धर्म संस्कृति और धरोहर ने

जाति-जनगणना के बाद बहुत काम



यह बात पाठकों को पता ही है कि मैंने हाल ही में जाति-जनगणना के ईद-गिर्द हो रही बातचीत के संदर्भ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पत्र के माध्यम से संपर्क किया था। संविधान की नौवीं अनुसूची में बड़े हुए राज्य आरक्षण कोटा को शामिल करने की मेरी मांग पर मुख्यमंत्री की चुप्पी ने एक बार फिर सामाजिक न्याय के मुद्दों पर एनडीए की तथाकथित डबल इंजन सरकार के पाखंड को उजागर कर दिया है।

उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। यह स्पष्ट रूप से गरीबों, शोषितों, और हाशिये पर पड़े लोगों के प्रति उनकी गहरी वैचारिक विपन्नता को दर्शाता है। दरअसल, राष्ट्रव्यापी जाति-जनगणना के संदर्भ में एनडीए की अनिच्छा राजनीतिक, वैचारिक और चुनावी गणनाओं के संयोजन में अंतर्निहित रही। भाजपा को यह मुद्दा असहज करता था, क्योंकि उनकी राजनीति एकांगी धार्मिक पहचान बनाकर ध्रुवीकरण की रही है। उसे डर था और है भी कि व्यापक जाति-जनगणना जाति आधारित असमानताओं पर टोस आंकड़े पेश करेगी, जिससे सार्वजनिक नीति में जाति की प्रासंगिकता मजबूत होगी, जो भाजपा के काल्पनिक विकास के पसंदीदा आख्यान के विपरीत है।

भाजपा का शोर्ष नेतृत्व और महत्वपूर्ण वोट आधार, विशेष रूप से हिंदी पट्टी में दबदेवा वाली जातियों के ईद-गिर्द ही रहा है। जाति-जनगणना ओबीसी, एससी और एसटी के प्रतिनिधित्व व सत्ता तक उनकी पहुंच से दूरी को उजागर कर देगी। भाजपा को डर है कि जाति-जनगणना से जनसंख्या अनुपात के आधार पर आरक्षण बढ़ाने की मांग बढ़ सकती है। यह डर सामाजिक न्याय के लिए हमारी वैध मांगों के प्रति उनके प्रतिरोध को प्रेरित करता है। विस्तृत जाति डाटा ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित और हाशिये पर पड़े समूहों को आरक्षण पुनर्गठन और लक्षित कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक शक्तिशाली चुनावी और नीतिगत हथियार प्रदान करेगा। हमारे जैसे विपक्षी दल जाति-जनगणना के लिए

तन और मन की लड़ाई में हमें विजयी बनाएगा योग

आमतौर पर पचास या साठ की उम्र तक आपको कोई समस्या नहीं आती है। उसके बाद असली समस्या तब होती है, जब शरीर के ऊतक भार सहन नहीं कर पाते। मैं जो अभ्यास अब करता हूँ, वह उससे कहीं ज्यादा कठिन है, जो मैं युवा होने पर करता था या सीखने के लिए संघर्ष करता था। हालाँकि, आज मैं उन अभ्यासों को बहुत कठिन नहीं मानता। हालाँकि, मैं तब प्रतिदिन दस घंटे अभ्यास करता था। आज यह शरीर और मन के बीच एक बड़ी लड़ाई है। शरीर कहता है, मैं यह नहीं कर सकता। मन कहता है, मुझे पर दबाव मत डालो।

मेरा विश्वास करें, एक निश्चित उम्र के बाद आसन और प्राणायाम का अभ्यास बहुत कठिन हो जाता है। हड्डियाँ भंगुर हो जाती हैं। रक्त वाहिकाएं सख्त हो जाती हैं। ये सभी ज्ञात तथ्य हैं। मैं इनका शिकार नहीं बना चाहता। अगर मैं शरीर की इच्छा के आगे समर्पण कर दूँ, तो मैं योगाभ्यासी नहीं रह जाता। जब मैं अभ्यास करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि इस क्षय प्रक्रिया को कैसे रोका जाए। यही इच्छाशक्ति का प्रभाव है। फिर आप कहते हैं, अयंगर को किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले अभ्यास किया है, लेकिन यह सोचने का सही तरीका नहीं है। वास्तव में, मैं देखता हूँ कि इस उम्र में मुझे कैसे अभ्यास करने की जरूरत है। मुझे संकुचन से बचना है। मैं प्रत्येक आसन में शरीर की पूर्ण ताजगी, दृढ़ता, बुद्धि की सजगता, स्थिरता और आत्मा की मधुर उदरता देखता हूँ।

अक्सर लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में उन्हें आसन और प्राणायाम के बजाय ध्यान या जप करना चाहिए। मैं बुढ़ापे की आड़ में शरण लेने वाला साधक नहीं हूँ। मैं बुढ़ापे के डर से अपने अभ्यास से भाग नहीं सकता। मैं प्रत्येक आसन में ध्यान करता हूँ, क्योंकि प्रत्येक आसन में मैं ईश्वर को देखता हूँ, जो अन्त है और माप से परे है। उम्र बढ़ने के कारण मैंने अपने अभ्यास में समय बढ़ा दिया है। मन और शरीर आराम करना चाहते हैं। मैं प्रतिदिन अपने शरीर और मन को इच्छा शक्ति के साथ खड़ा होने के लिए प्रेरित करता हूँ, ताकि मैं अपने शरीर और मन की कमजोरी के आगे न झुक जाऊँ।

दर्शनशास्त्र की अच्छी जानकारी होने के कारण, योग का अभ्यास करते हुए, मैं अब किसी पर निर्भर हुए बिना जीवन जी रहा हूँ। मुझे शरीर के दर्शन पर ही टिके रहना है, क्योंकि मैं पहले से ही आध्यात्मिक ज्ञान में डूबा हुआ हूँ।

विश्व को बहुत कुछ ऐसा दिया है, जो ईंसान को अच्छे मार्ग कि ओर अग्रसर करता है। इन्हीं में से एक है योग विधि, जिसे अपनकर ईंसान तन-मन से स्वस्थ होता है। योग मात्र शरीर को ही दुरुस्त नहीं करता, बल्कि मानसिक तौर पर भी स्वस्थ बनाता है। यह ईंसान का प्रकृति से भी तालमेल बढ़ाता है। आज बहुत से लोगों को शारीरिक और मानसिक, दोनों तरह की बीमारियों ने जीना दुश्चढ़ किया हुआ है। आज की भागदौड़ और भौतिकतावाद में ईंसान इतना व्यस्त हो गया है कि अपने शरीर की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता और बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। अगर लोग योग को अपना लें, तो वे अपने शरीर को चुस्त-दुरुस्त रख सकते हैं। ख्याल रखना होगा कि योग भी निरोग बनाएगा, जब योग के साथ-साथ खानपान और जीवनशैली भी सुधार हो।

👉 **राजेश कुमार चौहान**, टिप्पणीकार

यह जनगणना जातिगत असमानता के टोस आंकड़े पेश करेगी, जिससे सार्वजनिक नीति में जातियों की प्रासंगिकता मजबूत होगी, फिर हमें आरक्षण का दायरा बढ़ाना होगा।



जोर दे रहे हैं, क्योंकि यह संविधान में की गई प्रतिबद्धताओं को मजबूत करता है। जाति-जनगणना आरक्षण को इस तरह से पुनर्गठित करने के लिए अनुभव-जन्य आधार प्रदान करती है, जो जमीनी स्तर पर वास्तविक सामाजिक-आर्थिक हकीकत को दर्शाती है। इससे समानता व सामाजिक न्याय का सांविधानिक वादा पूरा होता है।

यही कारण है कि मैं बिहार में आरक्षण को बढ़ाकर 85 प्रतिशत करने के लिए नए कानून के जरिये टोस कार्रवाई की मांग कर रहा हूँ। हमें नौवीं अनुसूची के माध्यम से केंद्र के समर्थन की आवश्यकता है, क्योंकि सांविधानिक संरक्षण के बिना, इन प्रगतिशील उपायों को चुनौती दी जा सकती है और इनको कमजोर किया जा सकता है। न्यायपालिका द्वारा लगाई गई 50 प्रतिशत की अवैज्ञानिक सीमा को चुनौती देने की जरूरत है, जो न तो लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है और न ही हमारी सामाजिक संरचना का।

कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जाति-जनगणना के आंकड़े भारत के अत्यधिक विषम

विकास के मानचित्र को सुधारने के लिए आवश्यक हैं, जिसमें कुछ समूहों को लगातार बड़ा हिस्सा प्राप्त हो रहा है। आरक्षण नीति को समकालीन जनसांख्यिकीय व सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के हिसाब से न्यायोचित बनाने की आवश्यकता है। जाति-जनगणना अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के भीतर विभिन्न उप-समूहों के वास्तविक प्रतिनिधित्व और अभाव के स्तर पर अनुभवजन्य स्पष्टता प्रदान करेगी। इस जनगणना के निष्कर्षों के आधार पर आरक्षण का बढ़ा हुआ कोटा शिक्षा, रोजगार और शासन में हाशिये पर पड़े समुदायों के ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक उपाय के रूप में काम करेगा। साथ ही, निजी क्षेत्र को उनकी रोजगार नीति में विविधता को प्रतिबिंबित करने में भी मदद करेगा।

मुझे इस बात से परेशानी है कि केंद्र सरकार लंबे समय से इस मुद्दे पर कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखा रही है। मैंने बिहार की राजनीति में इस दोहरपन को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। भाजपा चुनावों के दौरान पिछड़े वर्गों को

मनसा वाचा कर्मणा संगीत भी एक साधना

भारत में संगीत क्षणिक आमोद-प्रमोद व अतुल तृष्णा की वस्तु न होकर समस्त ब्रह्मांड अथवा व्यक्त जगत से ऐक्य का आभास है, चिरानंद प्रदान करने वाली आध्यात्मिक साधना है और सांसारिक दुखों से मुक्ति प्रदान करने व ब्रह्म तक मानव को ले जाने वाला मार्ग है। संसार में संभवतः ऐसा अन्य कोई देश नहीं, जहां संगीत इतने पुराने युग से जनजीवन में इतना व्याप्त हो, जितना वह भारत में सहस्रों वर्षों से रहा है।

संसार की सभी जातियों की अपेक्षा भारतवासियों के कहीं अधिक संगीतप्रेमी होने की बात का जिक्र मेगस्थनीज भी कर गया है। ईसा पूर्व 150 के लगभग लिखे गए *इंडिका* नामक अपने ग्रंथ में आर्यन ने मेगस्थनीज का यह कथन उद्धृत किया है कि सब जातियों की अपेक्षा भारतीय लोग संगीत के कहीं अधिक प्रेमी हैं। भारत में संगीत ने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में वह काम किया है, जो संभवतः अन्य कोई शक्ति शताब्दियों के परिश्रम के पश्चात भी न कर पाती।



सद्गुरु जगगी वासुदेव आध्यात्मिक गुरु

कोई भी काम तनावपूर्ण नहीं होता। यह आपके शरीर, मन और भावनाओं को नियंत्रित करने में आपकी अक्षमता है, जो इसे तनावपूर्ण बनाती है। ध्यान आपके अस्तित्व की सुंदरता को महसूस करने का एक साधन है।

हानिकारक है। गर्भावस्था वाली महिलाएं, हृदय रोग या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों को योग करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा, अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो योग करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। योग के तुरंत बाद नहाना या ठंडा पानी पीना शरीर के लिए हानिकारक है। यदि आप योग से होने वाले संभावित नुकसानों के बारे में चिंतित हैं, तो किसी योग्य योग शिक्षक से सलाह लेना सबसे अच्छा है। एक अनुभवी शिक्षक आपको सही तरीके से योग करने व अपनी शारीरिक सीमाओं का सम्मान करने में मदद कर सकते हैं।

👉 **चनानंद जायस**, टिप्पणीकार
आज की भागमभाग भरी ज़िंदगी में लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं है। जीवन शैली इतनी बदल गई है कि आदमी हंसना तक भूल गया है। नशा, बुरी लतों आदि ने

समर्थन देने की बात करती है, लेकिन जब हमारे 85 प्रतिशत आरक्षण की मांग का समर्थन करने या नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए दबाव बनाने जैसी टोस कार्रवाई की बात आती है, तो वे चुप्पी साध लेते हैं। न्यायपालिका के गलियारों में छद्म संगठनों द्वारा इसे विफल करने के प्रयास किए गए। यदि भाजपा और एनडीए के उनके सहयोगी, विशेष रूप से बिहार में, लगभग बीस वर्षों तक शासन करने के बाद इतना कुछ नहीं कर सके हैं, तो हाल ही में घोषित आधी-अधूरी राष्ट्रीय जाति-जनगणना के बाद उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। भाजपा की समग्र अनिच्छा न तो प्रशासनिक चुनौतियों से और न ही तार्किक चुनौतियों उपजती है, बल्कि यह राजनीतिक आशंकाओं की उपज है : जाति-जनगणना उसके उस सामाजिक गठबंधन को उलट सकती है, जिस पर वह निर्भर है। यह गणना सामाजिक न्याय की अधूरी चिंताओं को पुनर्जीवित कर सकती है और भारतीय समाज के वैचारिक ढांचे को चुनौती दे सकती है।

जैसा कि हम सब जानते हैं, एक पूर्ण, पारदर्शी जाति-जनगणना भाजपा के लिए असहज सच्चाई प्रस्तुत कर सकती है, जिसे अब वह घुमा-फिराकर या दबाकर नहीं रख सकती। जाति के आंकड़े विभिन्न जाति समूहों व उप-समूहों की वास्तविक संख्या तो बताएंगे ही, विभिन्न क्षेत्रों में उनके प्रतिनिधित्व को प्रकट करेंगे, जिससे भाजपा के लिए वास्तविक सशक्तिकरण को नकारते हुए अपनी बयानबाजी तक उसे सीमित रखना असंभव हो जाएगा। बिहार में आरक्षण-सीमा में वृद्धि व विशेष विधानसभा सत्र की मेरी मांग दरअसल पारदर्शिता और न्याय की इस बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। मेरी अपील है कि हम खोखले वादों से आगे बढ़कर टोस विधायी कार्रवाई करें, जो सांविधानिक संरक्षण के माध्यम से न्यायिक जांच का भी सामना कर सके।

सभी राजनीतिक दलों के लिए यह चुनने का समय आ गया है कि वे समानता के सांविधानिक वादे के साथ खड़े हैं या उन ताकतों के साथ हैं, जो ऐतिहासिक विशेषाधिकारों के संरक्षित करना चाहते हैं। व्यापक जाति-जनगणना एक सच्चे लोकतंत्र के निर्माण की दिशा में पहला कदम है, जिसकी नीतियां तथ्यों पर आधारित होती हैं, जहां संसंधनों का उचित आवंटन होता है और प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र की प्रगति में उसका उचित स्थान मिलता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा संगीत भी एक साधना

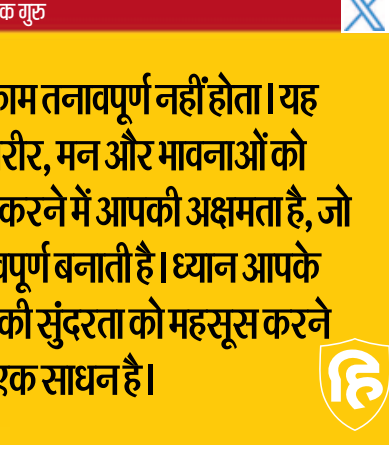
हमारा साधारण जन इस प्रकार का ज्ञान रखता है, तो उसका एक प्रमुख कारण यही है कि संगीतमय गथाओं और कथाओं ने उसके हृदय में उस ज्ञान को बैठा दिया है। मैं कभी-कभी सोचा करता हूँ कि क्या कारण है, भारत ही एक ऐसा देश है, जिसमें तुलसी या कबीर जैसे कवियों की कृतियों से अनपढ़ लोग भी करोड़ों की संख्या में परिचित हैं। पर मैं समझता हूँ कि इस रहस्य का हल यही है कि हमारे जीवन में इतना बुरा हुआ है कि सहज में ही

भारत में संगीत ने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में वह काम किया है, जो संभवतः अन्य कोई शक्ति शताब्दियों के परिश्रम के पश्चात भी न कर पाती।

इन कवियों के मधुर पद घर-घर और ग्राम-ग्राम की संपत्ति बन गए। आज भी ऐसे अनेक लोग मिल जाएंगे, जो अनपढ़ होते हुए भी *श्रीरामचरितमानस* के पद सादर सुना सकते हैं, और कबीर के पदों का तो कहना ही क्या है?

अतः भारत के सांस्कृतिक-आध्यात्मिक विकास में संगीत का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हमारे देश के प्राचीन युग में संगीत शास्त्रियों और संगीतज्ञों का भी बड़ा ऊंचा दर्जा होता था, जैसा कि संगीत शास्त्रियों की मुनि और ऋषि की उपाधियों से पूर्णतया स्पष्ट है।

डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद



कोई भी काम तनावपूर्ण नहीं होता। यह आपके शरीर, मन और भावनाओं को नियंत्रित करने में आपकी अक्षमता है, जो इसे तनावपूर्ण बनाती है। ध्यान आपके अस्तित्व की सुंदरता को महसूस करने का एक साधन है।

व्यक्ति को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया है। ऐसे में मानव जीवन का असली मूल्य ही खो गया है। पैसा ही आदमी का मुख्य मकसद हो गया है। इसी वजह से वह अवसाद ग्रस्त भी होता है। मानव जीवन को हर तरह की गतिविधियों की आवश्यकता है। ऐसे में, अगर मनुष्य जीवन का असली आनंद लेता है, तो तनाव से मुक्त होकर हास्य के साथ ही तनाव मुक्त जीवन जीना होगा। लेकिन इसके लिए समय कहाँ है? हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है, नौकरी-पेशा की ऐसी भागमभाग है कि एक मिन्ट की भी फुर्सत नहीं मिल पाती। प्रकृति के अनुसार खान-पान, रहन-सहन और आचार-विचार भी नहीं मिलते। तो व्यक्ति स्वस्थ, मजबूत और दीर्घायु कैसे रह सकता है? आज जिस तरह लोगों की दिनचर्या हो गई है, वह वास्तव की नहीं, जानलेवा हो गई है।

👉 **अमृतलाल मारू 'रवि'**, टिप्पणीकार

